● वर्ष-4
● अंक-183
रायपुर, बुधवार
12 मार्च 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल....

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

नई दिल्ली । मॉरीशस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला 21वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की। पीएम मोदी मॉरीशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रामगुलाम ने पोर्ट लुईस में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में ये घोषणा की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी आज दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरीशस पहुंचे, जहां उनका स्वागत रामगुलाम ने किया। दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया। पीएम श्री मोदी कल

मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रुप में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी समारोह में भाग लेगी। इसके अलावा वह द्वीप राष्ट्र में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से नई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे।

पीएम श्री मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखुल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मॉरीशस के राष्ट्रपति को कई चीजें भेंट की है, जिसमें महाकुंभ से संगम का जल और सुपर फूड मखाना भी शामिल है। इसके अलावा पीएम श्री मोदी ने गोखुल की पत्नी वृंदा गोखुल को बनारसी सिल्क की साड़ी भी भेंट की है।

मॉरीशस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वे भारत और भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह परिचित हैं। मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की.

एक अन्य ट्वीट में पीएम श्री मोदी ने कहा, ये सराहनीय है कि मॉरीशस के स्टेट हाउस में आयुर्वेदिक गार्डन बनाया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मॉरीशस में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है। राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल और मैं आयुर्वेदिक गार्डन गए, जिससे मुझे इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 साल बाद मॉरीशस के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साल 2015 मार्च में मॉरीशस गए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए थे। मॉरीशस और भारत का पुराना रिश्ता रहा है।

भारत के लिए मॉरीशस की कूटनीतिक अहमियत

कीर्तिवर्धन मिश्र

मौजूदा समय में मॉरीशस की 12 लाख की आबादी में से करीब 70 फीसदी जनसंख्या भारतवंशियों की है। वहीं, मॉरीशस में धर्मों की बात करें तो यहां हिंदू धर्म को मानने वाले करीब 48 प्रतिशत हैं, इसके बाद 32 फीसदी ईसाई, 18 फीसदी मुस्लिम और 1.6 फीसदी अन्य धर्म के लोग हैं।

मॉरीशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेने गए हैं, उसका भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सीधा जुड़ाव है। दरअसल, 1901 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सफलतापूर्वक आंदोलन कर के भारत लौट रहे थे, तब वे कुछ समय के लिए मॉरीशस में भी रुके थे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन वाले मॉरीशस में बसे भारतवंशियों से बात की थी और उन्हें बदलाव के तीन संदेश दिए थे। इसके तहत गांधी ने भारतीयों को शिक्षा का महत्व, राजनीतिक सशक्तीकरण और भारत से जुड़े रहने का मंत्र दिया था। हिंद महासागर के जरिए सीधा जुड़ाव होने की वजह से भारत के लिए मॉरीशस की कूटनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। 2015 में जब प्रधानमंत्री मॉरीशस के पहले दौरे पर गए थे, तब दोनों देशों ने मॉरीशस के अगलेगा द्वीप पर परिवहन व्यवस्था बेहतर करने के लिए समझौता किया। दरअसल, यह द्वीप मॉरीशस के मेनलैंड से करीब 1100 किमी दूर स्थित है और भारत के भूमि क्षेत्र के करीब है। यह छोटा टापू करीब 70 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है और भारत की सुरक्षा के मद्देनजर अहम है। फरवरी 2024 में भारत और मॉरीशस ने इस द्वीप पर एक एयर स्ट्रिप और जेटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, जो कि क्षेत्र में भारत की रक्षा के लिहाज से बड़ा कदम साबित हुआ। इतना ही नहीं चीन की कब्जे वाली नीति को देखते हुए मॉरीशस से दूर स्थित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी यह प्रोजेक्ट अहम है।

रक्षा से शिक्षा तक, मॉरीशस के साथ गहरे हैं भारत के रिश्ते: 1. रक्षा: भारत और मॉरीशस रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। भारतीय नौसेना समय-समय पर आपदाओं और सैन्य अभियानों में मॉरीशस की मदद करती रही है। माना जा रहा है कि इस बार भी भारत और मॉरीशस अपने व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश रियल टाइम डाटा साझा करने पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिससे हिंद महासागर में सुरक्षा के पैमाने मजबूत होंगे।

2. व्यापार: मॉरीशस के लिए भारत से व्यापार एक लाइफलाइन के तौर पर देखा जाता है। सिंगापुर के बाद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में मॉरीशस दूसरे स्थान पर है। दोनों देश 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता भी कर चुका है। यह किसी अफ्रीकी देश से भारत का पहला व्यापार समझौता रहा।

3. शिक्षा : भारत और मॉरीशस के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग है। मौजूदा समय में करीब 2300 भारतीय छात्र-छात्राएं मॉरीशस में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यह स्टूडेंट्स चिकित्सा, होटल मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज जैसे क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

दूसरे धर्मों की लड़कियों की हो घर वापसी

नईदिल्ली। युवा ब्रिगेड के संस्थापक चक्रवर्ती सुलीबेले ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक हिंदू संगठन के कार्यक्रम में कहा कि सिर्फ़ लव जिहाद के बारे में बात करने के बजाय, लोगों को आक्रामक तरीके से घर वापसी (पुन: धर्मांतरण) के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरे धर्मों की लड़कियों को अपने धर्म में लाना चाहिए। सुलीबेले ने मंगलुरु में एक कार्यक्रम में यह बात कही। कार्यक्रम में बोलते हुए सुलीबेले ने तर्क दिया कि अन्य धर्मों की लड़कियों को हिंदू धर्म में लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए

और इस उद्देश्य के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का आग्रह किया।

सुलीबेले ने कहा कि हम कब तक कहते रहेंगे कि धर्म परिवर्तन हो रहा है? अब बदलाव का समय है। अब हम %घर वापसी% के बारे में बात करेंगे। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो खुद कार्रवाई करने के बजाय विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को धर्म परिवर्तन की सूचना देते हैं। 卐वीएचपी नेताओं को बुलाकर शिकायत करने के बजाय कि किसने उनका धर्म परिवर्तन किया, आपको खुद ही उनका धर्म परिवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। सुलीबेले ने इस उद्देश्य के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है -बस ऐसे व्यक्ति को मंदिर में ले जाएं, उनसे हाथ जोड़ने को कहें और उनसे कहें, %मैंने गलती की है।% इसे खबर बनानी चाहिए।

उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह के कृत्यों को बढ़ावा देने को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, 卐हमारे युवा बेतरतीब चीजों पर रील बनाते हैं; अब उन्हें %घर वापसी% पर रील बनानी चाहिए।卐 अंतर-धार्मिक संबंधों के विषय को संबोधित करते हुए सुलीबेले ने दृष्टिकोण में बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, 卐हम कब तक %लव जिहाद% के बारे में बात करते रहेंगे? अब इसे भी बदलने का समय आ गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से लिया आशीर्वाद

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में आध्यात्मिक गुरु एवं द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए श्री श्री रविशंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकस्वरूप, जशपुर जिले में स्थित विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग - मधेश्वर पहाड़ का छायाचित्र एवं बस्तर आर्ट शैली में निर्मित नंदी की प्रतिकृति भेंट कर श्री श्री रविशंकर का अभिनंदन किया।श्री श्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री श्री साय को अवगत कराया कि इस बार वे अपने साथ 1000 वर्ष पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित शिवलिंग के अवशेष लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक शिवलिंग के अवशेष को सदियों से एक अग्निहोत्री परिवार द्वारा सुरक्षित रखा गया था।

प्रमुख समाचार

हम सब भारत के लाल, भेदभाव का कहां सवाल: शिवराज

नईदिल्ली। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और भाजपा के बीच वार-पलटवार के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया है। शिवराज ने संसद में कहा कि मैं खुद दो बार तमिलनाडु गया हूं, एक बार कृषि विभाग के काम से और एक बार ग्रामीण विकास के काम से। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन दोनों ही मौकों पर न तो ग्रामीण विकास मंत्री और न ही कृषि मंत्री मेरी बैठक में आए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई नाम शेष है तो हमें बताए, मैं खुद वहां चला जाउंगा। उन्होंने कहा कि हमसब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु के महान लोगों को सलाम करते हैं, तमिल संस्कृति को सलाम करते हैं, तमिल भाषा को सलाम करते हैं, हम सभी भारत माता के बेटे हैं, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। हम विनम्रता के साथ तमिलनाडु के लोगों और किसानों की सेवा करेंगे।

मुझे विभीषण की तरह लंका से निकाला गया: कीर्ति

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने आज अपनी पुरानी पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा में आरोप लगाया कि एक घोटाले को उजागर करने के लिए पार्टी ने उन्हें उसी तरह से निकाला जैसे विभीषण को लंका से बाहर किया गया था। दरअसल, लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और 2025-26 के लिए मणिपुर के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर आज चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा में बोलने के लिए आजाद खड़े हुए थे। कभी भाजपा के सांसद रहे आजाद पार्टी ने निकलने का बाद कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने सदन में भाजपा सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, ''मुझसे बेहतर इन लोगों को कोई नहीं जानता। मैंने क्रिकेट में 400 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले को उठाया तो मुझे 'विभीषण की तरह लंका से निकाल दिया गया।'' आजाद ने अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

महिलाओं को डर के साये में नहीं रहना चाहिए: रेखा

नयी दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को यहां एक कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और पैरालिंपियन सहित सात महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने एक दैनिक अखबार की ओर से आयोजित एक महिला बाइक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिला बाइक चालक सशक्तीकरण का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, %आपने उन लोगों को गलत साबित कर दिया है जो कहते हैं कि महिलाएं कुछ चीजें नहीं कर सकतीं।सम्मानित होने वाली सात महिलाओं में जम्मू-कश्मीर की पहली अंतरराष्ट्रीय कार रेसर हुमैरा मुश्ताक, अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान दिव्या काकरान, घरेलू हिंसा से पीड़ित और समान संघर्ष वाली महिलाओं के लिए गैर सरकारी संगठन की स्थापनाकरने वाली स्वीटी मेहता, मादक पदार्थों के लती लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यापक रूप से काम करने वाली रेखा जिंदल, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को कंप्यूटर सिखाने के लिए खुद को समर्पित करने वाली नलिनी अस्थाना, पैरा एथलीट कंचन लखानी और सामाजिक कार्यकर्ता नीतू चौधरी शामिल थीं।बाइक रैली रविवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे कॉनॉट प्लेस से शुरू हुई। गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम 2013 से हर साल आयोजित किया जा रहा है।

ग़रीबों में क्यों नहीं बांटा जा रहा मंदिरों का सोना-चांदी : मौलाना

नईदिल्ली। प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इसने अपने विचार-विमर्श में त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, धर्मगुरु ने कहा कि सभी वक़्फ़ संपत्तियाँ सार्वजनिक संपत्ति हैं क्योंकि जनता ने उन्हें अच्छे कामों के लिए दान किया है। वक़्फ़ बोर्ड सिर्फ़ चौकीदार है, मालिक नहीं। जैसे केंद्र सरकार भारत की चौकीदार है, मालिक नहीं। आप कश्मीर का नियंत्रण किसी और को, पाकिस्तान को नहीं दे सकते क्योंकि सरकार देश की मालिक नहीं बल्कि चौकीदार है। नकवी ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि आप वक़्फ़ के लिए कह रहे हैं कि इससे ग़रीबों को फ़ायदा होगा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 5 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं और मंदिरों में हज़ारों टन सोना-चाँदी है। इसे ग़रीबों में क्यों नहीं बांटा जा रहा? इन मंदिरों में इतना सोना है कि अगर इसे बाँट दिया जाए तो हर ग़रीब हिंदू अमीर बन जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर ये सोना वापस रिजर्व बैंक में चला जाए तो डॉलर 20 रुपये पर आ जाएगा और महंगाई खत्म हो जाएगी।

एक ही बजट में पूरे नहीं कर सकते सभी वादे : उमर अब्दुल्ला

नईदिल्ली। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि वे अपनी पार्टी द्वारा चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी यह वादा नहीं किया था कि वे एक बजट में ही उन्हें पूरा कर देंगे। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस बजट के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि वे सभी वादे पूरे करेंगे। मुख्यमंत्री उमर ने पूछा, अगर हमने सबसे गरीब लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है तो इसमें क्या गलती है?पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन की चिंताओं का जवाब देते हुए सीएम उमर ने कहा कि बजट का महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने पीडीपी-बीजेपी के बजट भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए कुछ नहीं किया और उनके शासन में केवल 570 लोगों को नियमित किया गया। उन्होंने दैनिक वेतनभोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की भी घोषणा की।

इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 लोकसभा में पेश

आव्रजन कानूनों को सरल बना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा नया कानून

नईदिल्ली। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन जबरदस्त तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार का दौर देखा गया। हालांकि कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हुई। साथ ही साथ सवाल जवाब ही हुए। इसी कड़ी में संसद में आज इमीग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया गया। इसके अलावा डे कैंसर केयर सेंटर की भी सरकार की ओर से बात की गई है। आईए, दोनों विषयों को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है?

इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025

सरकार ने आज इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 को आज लोकसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य आव्रजन कानूनों को सरल बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और उल्लंघनों के लिए कठोर दंड लगाना है। चार अधिनियमों- पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त कर एक व्यापक अधिनियम बनाया जा रहा है। विपक्ष के कुछ सदस्यों के विरोध के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पेश किया।

आम जनता से कैसे जुड़ा ये बिल

राष्ट्र हर नागरिक के लिए एक भावनात्मक मुद्दा होता है। हर नागरिक चाहता है कि राष्ट्र सुरक्षित रहे। हालांकि हमने देखा है कि कैसे दूसरे देशों से आने वाले लोग हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं जबकि उनके पास हमारे देश का कोई ठोस दस्तावेज नहीं होता है। ऐसे ही लोगों को नियंत्रित करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल देश में दाखिल होने वाले और यहां से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या बाकी यात्रा दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशों से संबंधित मामलों को रेगुलेट करने की शक्तियां केंद्र सरकार को देगा।

यह विधेयक स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश या निवास पर पाबंदी लगाता है। इस

विधायक के जरिए कानूनी स्थिति साबित करने की जिम्मेदारी राज्य के बजाय व्यक्ति पर डाल दी गई है। इसके अलावा नियम तोड़ने पर कड़ी सजा भी हो सकती है। हालांकि विपक्ष इस बिल को पूरी तरीके से मूलभूत अधिकारों का हनन बता रहा है। इसका कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति जायज काम से भी भारत आ रहा है तो उसे तमाम जानकारी मुहैया करानी होगी। मान के चलिए की अगर कोई विदेशी नागरिक अस्पताल में भर्ती होने के लिए भारत आ रहा है तो उसका पुरा ब्योरा मांगा जा सकता है। कांग्रेस का ढावा है कि यह मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। हालांकि कानून तो आ गया। संसद में पास भी करा लिया जाएगा। लेकिन यह अमल में कितना लाया जाता है, देखने वाली बात होगी।

डे कैंसर केयर सेंटर

स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक देश में 200 'डे कैंसर केयर सेंटर' खोलने का है, जहां मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और अगले तीन सालों में सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2025-26 में हम 200 'डे कैंसर केयर सेंटर' खोलने जा रहे हैं और अगले तीन वर्षों में देश के सभी जिलों में ऐसे सेंटर खोले जाएंगे।'' उन्होंने यह भी घोषणा की कि 22 एम्स में पूर्ण ऑन्कोलॉजी विभाग हैं और सभी केंद्रीय अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिए ऑन्कोलॉजी विभाग हैं।

आम जनता के लिए मददगार कैसे: एक नए अध्ययन ने भारत में समग्र स्वास्थ्य में गिरावट की एक चिंताजनक तस्वीर सामने लाई है। एक रिपोर्ट में पाया गया कि देश भर में कैंसर और अन्य गैर-संचारी रोगों के मामलों में बेतहाशा वृद्धि ने अब इसे दुनिया की कैंसर राजधानी बना दिया है। हर साल लाखों नए मामले सामने आते हैं और इनमें से कई लोगों अपनी जान गवानी पड़ती है। देश में कैंसर का खतरनाक स्तर पर जाने का बड़ा कारण जागरूकता की कमी और शुरुआती इलाज में लापरवाही को माना जा सकता है। इसके अलावा कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। 30 से 40त्न लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाते। ऐसे लोगों के लिए डे कैंसर केयर सेंटर काफी मददगार साबित हो सकता है।

सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर स्वास्थ्य सेवा को किफायती, सुलभ और न्यायसंगत बनाने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू हो सकता है।

सिविल सर्जन के खिलाफ डॉक्टरों ने खोला मोर्चा

ओपीडी छोड़ साइकिल स्टेंड पर मरीजों का इलाज, डॉक्टरों का आंदोलन तेज

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिला के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के खिलाफ डॉक्टरों ने आंदोलन तेज कर दिया है। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल की ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है।हाथ में काला फीता बांध कर जिला अस्पताल के साइकिल स्टेंड में अलग ओपीडी शुरू कर दी है। जमीन पर बैठ कर मरीजों का उपचार कर रहे हैं।

डॉक्टर अपने चेम्बर को छोड़ कर साइकिल स्टेण्ड से मरीजों का नि:शुल्क इलाज कर रहे हैं। एक मरीज के परिजन मनबोध साहू ने बताया कि पैर में सूजन की वजह से चेक कराने आए हैं। चेकअप कराया है। दवाई लिखे हैं।

मरीजों को आंदोलनकारी डॉक्टरों की पर्ची से जिला अस्पताल से ना तो दवा मिल रही है और ना ही कोई जांच हो रही है। वहीं डॉक्टरों के आंदोलन को देखते हुए सिविल सर्जन ने खुद ही ओपीडी संभाल ली है। सिविल सर्जन और एक डॉक्टर ओपीडी के अंदर इलाज कर रहे हैं।

आंदोलन में शामिल जिला अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉ पुष्पेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि हर साल 800-900 कैंसर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हर साल 300-400 कीमोथैरेपी की सुविधा दे रहे हैं। जिला अस्पताल की मंथली ओपीडी 15 से 20 हजार है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी नियम के मुताबिक काम कर रहे हैं।

डॉ पुष्पेंद्र पटेल कहते हैं कि डर कर काम नहीं करना चाहते हैं। हमें कठोर कदम उठाना पड़ा लेकिन अब भी हम मरीजों को चेक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल मिले ताकि हम बेहतर इलाज कर सकें।

दरअसल जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में एक सप्ताह से सिविल सर्जन और डॉक्टर के साथ स्टॉफ नर्स का विरोध जारी है। सिविल सर्जन दीपक जायसवाल पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ का अपमान करने और जिला अस्पताल में तनाव पूर्ण माहौल बनाने का आरोप है। अब डॉक्टर शासन प्रशासन से सिविल सर्जन को हटाने की मांग कर रहे है।

छत्तीसगढ़ डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ इकबाल हुसैन ने कहा कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन पर विचार करेंगे। सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी संघ के बीच आंदोलन को लेकर बैठक भी है, जिसमें आंदोलन को लेकर चर्चा होनी है।

शीशल कला को बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा रही शोभा बघेल

जगदलपुर। बस्तर अंचल विभिन्न शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध है जहां काष्ठ कला, टेराकोटा, बेलमेटल, लौह शिल्प इत्यादि के विख्यात शिल्पकार अपनी अमिट पहचान स्थापित कर चुके हैं। इसी क्रम में बस्तर जिले के विकासखण्ड बस्तर के परचनपाल निवासी शोभा बघेल शीशल कला की हुनर को एक नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। शोभा जहां स्वयं शीशल रस्सी से डायनिंग मेट, पी-कोस्टर, नाव, झूमर, गुडिया, बास्केट, साईड पर्स, झूला, दिवाल इंजिन, लेटर होल्डर आदि कलात्मक वस्तुएं तैयार कर विक्रय कर रही हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों को शीशल कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बना रही हैं।

शोभा अपनी कलात्मक वस्तुओं को शबरी एम्पोरियम सहित बिहान मड़ई, शिल्प महोत्सव, बस्तर मड़ई, चित्रकोट महोत्सव, स्थानीय बाजार, आमचो बस्तर बाजार, राज्य के आधुनिक मॉल तथा अन्य प्रदेशों के प्रदर्शनी, सरस मेला जैसे आयोजनों में विक्रय कर हर महीने 20 से 25 हजार रुपए आय अर्जित कर रही हैं और अपने घर-परिवार को खुशहाल बना चुकी हैं। अपनी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण आमदनी के जरिए शोभा ने अपने बेटे भगतसिंह बघेल को ग्रेजुएट तक पढ़ाई करवाया है तो बेटी पिंकी बघेल को बीएससी नर्सिंग की शिक्षा दिलवाई हैं। जिससे पिंकी अब जगदलपुर के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में स्टॉफ नर्स की सेवा देकर घर-परिवार की मदद कर रही हैं।

शोभा ने बताया कि वह अपने पति बंशी बघेल के साथ विभिन्न स्थानों में शीशल कला का ट्रेनिंग भी दे रही हैं जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों के साथ ही केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर, नवोदय विद्यालय जगदलपुर के छात्र-छात्राओं को शीशल कला का प्रशिक्षण प्रदान किया है।

टीआई पर लगा गंभीर लापरवाही का आरोप, आईजी ने किया सस्पेंड

बिलासपुर। पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला के निर्देश पर पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने कोनी थानेदार नवीन कुमार देवांगन को निलंबित कर दिया है। टीआई पर धारा 112/24, 268/24, 283/24, 302/24, 468/24, 22/25 और 34(2)आबकारी अधिनियम के तहत जांच में लापरवाही का गंभीर आरोप है।

दरअसल, बीते माह लोफंदी गांव में महुआ शराब पीने से नौ लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद एसपी ने अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने छापेमारी कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया। लेकिन केस डायरी में उनके आपराधिक हिस्ट्री को शामिल नहीं किया गया। इस चूक का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। जब यह मामला पुलिस के आला अफसरों के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इसे कोनी पुलिस की गंभीर लापरवाही माना। मामले में एसपी ने कोनी टीआई नवीन देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

ये है पूरा मामला

कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी में जहरीली महुआ शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई, यानी कुल 9 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी।

अद्भूत इंजीनियरिंग का रहस्य समेटे घाघरा मंदिर

■ **बिना जोड़ के पत्थरों से बनी रहस्यमयी संरचना**

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। जिले में स्थित घाघरा मंदिर अपने रहस्यमयी निर्माण और अनोखी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ के सिर्फ पत्थरों को संतुलित करके बनाई गई इस प्राचीन संरचना का झुका हुआ स्वरूप इसे और भी रोचक बनाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास और वास्तुकला का यह अनमोल रत्न आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है।

जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगभग 130 किलोमीटर दूर जनकपुर के पास स्थित इस मंदिर का रहस्य आज भी विशेषज्ञों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। सदियों पुराना यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं, जो बिना किसी गारा-मिट्टी या चूने के इस्तेमाल के आज भी मजबूती से खड़ा है।

घाघरा मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी निर्माण शैली है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर पत्थरों को संतुलित करके इस तरह खड़ा किया गया है कि किसी भी प्रकार की जोड़ने वाली सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यह तकनीक प्राचीन भारतीय वास्तुकला के अद्भुत कौशल को दर्शाती है। इस मंदिर का झुका हुआ स्वरूप इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। माना जाता है कि किसी भूगर्भीय हलचल या भूकंप के कारण इसका झुकाव हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद सदियों से यह मंदिर अपनी मजबूती के साथ खड़ा है।

घाघरा मंदिर के निर्माण काल को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकार इसे 10वीं शताब्दी का बताते हैं, तो कुछ इसे बौद्ध कालीन संरचना मानते हैं। वहीं, स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां आज भी विशेष अवसरों पर पूजा-अर्चना होती है। मंदिर के भीतर किसी भी मूर्ति का न होना इसके रहस्य को और गहरा करता है। कई स्थानीय कथाओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल का प्रमाण है।

घाघरा मंदिर केवल श्रद्धालुओं का आस्था स्थल ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी अनमोल प्रतीक है। इस अद्भुत संरचना को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक और शोधकर्ता आते हैं। पुरातत्वविदों के लिए भी यह मंदिर एक शोध का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मंदिर को उचित पहचान दी जाए, तो यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी प्रमुख कस्बा जनकपुर है, जहां से घाघरा गांव आसानी से पहुंचा जा सकता है। मनेंद्रगढ़ से यहां तक का सफर लगभग 130 किलोमीटर का है। सड़क मार्ग के जरिए इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का कोड़ातराई में दिखा असर

833 उपभोक्ताओं ने किया आवेदन, 69 घरों में लग चुके सौर संयंत्र

रायगढ़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों के बिजली खर्च को कम करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई में इस योजना ने कई परिवारों को राहत पहुंचाई है, जिससे वे हर महीने हजारों रुपये की बचत कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल लोगों के बिजली खर्च को कम कर रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। रायगढ़ जिले के कोड़ातराई ग्राम में इस योजना की सफलता भविष्य में अन्य गांवों के लिए भी अनुकरणीय होगी।

ग्राम कोड़ातराई के निवासी श्री जयनारायण चौधरी और श्री राजेश कुमार चौधरी जैसे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। श्री जयनारायण चौधरी ने बताया कि पहले उनका बिजली बिल हर माह 2000 से 2500 रुपये तक आता था, जब उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया। एक माह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित हो गया, जिसकी कुल लागत 1 लाख 90 हजार रुपये थी। उन्हें इस पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। इसी तरह, श्री राजेश कुमार चौधरी ने विद्युत विभाग से संपर्क कर आवेदन किया और एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लग गया। इस संयंत्र से हर माह 300 से 350 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उनका बिजली बिल काफी कम हो गया है। दोनों उपभोक्ताओं ने इस योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा प्रदान करना है। 29 फरवरी 2024 को लागू इस योजना के तहत सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता अपने घर की छत पर 1, 2 या 3 किलोवाट तक का सौर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को https://pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करना होगा। इससे औसतन 300 यूनिट तक की बचत के जरिए बिजली बिल में 2000 रुपये तक की कमी संभव है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत बैंक लोन भी उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ता को संयंत्र की लागत का 90 प्रतिशत तक बैंक लोन न्यूनतम 7 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल सकता है।

रायगढ़ जिले में अब तक 833 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 69 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित हो चुका है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई को आर्दश सौर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। यहां के 187 पात्र आवेदकों में से 46 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है और अब तक 4 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

अज्ञात जंगली जानवर ने किया शिकार

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वन मंडल के पेंड्रा वन परिक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां के पीपलामार गांव में ग्रामीणों ने खून में लथपथ एक मवेशी का शव देखा। मवेशी के शरीर में किसी बड़े अज्ञात जानवर के शिकार के निशान भी मिले हैं। ग्रामीण इसे बाघ के हमले की आशंका जता रहे हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मरवाही वन मंडल के पेंड्रा परिक्षेत्र स्थित पीपलामार गांव के रहने वाले चन्द्रभान सिंह की बाड़ी में एक मवेशी का खून से लथपथ शव मिला। शव पर अज्ञात जंगली जानवर के शिकार किये जाने के निशान मिले है। लेकिन अज्ञात जानवर कौन सा है यह स्पष्ट नहीं है। वही मृत मवेशी के शरीर में कई बड़े जख्म भी देखने को मिले है। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात डेढ़ से 3 बजे के बीच गांव में कुत्तों के भौंकने की काफी आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसी समय जंगली जानवर ने मवेशी का शिकार किया है। मवेशी के शिकार की जानकारी मिलते ही पेंड्रा वन परिक्षेत्र वन विभाग की टीम गांव पहुंची और जांच शुरू की।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

महिला कर्मचारी विश्राम कक्ष संगिनी का विधिवत शुभारंभ

बिलासपुर। महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर सुविधा विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कर्मचारी कल्याण निधि से मंडल कार्यालय कर्मचारी जलपान गृह में महिला कर्मचारी विश्राम कक्ष संगिनी कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस विश्राम कक्ष का विधिवत प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी डॉ. श्रीमती दर्शनीता बी.अहलूवालिया तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजमल खोईवाल की गरिमामयी उपस्थिती में संपन्न हुआ। यह पहल महिला कर्मचारियों के लिए आरामदायक और सुविधाजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विश्राम कक्ष में आवश्यकतानुसार सभी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे महिला कर्मचारियों को कार्य के दौरान विश्राम और सहजता का अनुभव हो सके। इस अवसर पर मंडल के वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी डॉ अंशुमान मिश्रा, मंडल कार्मिक अधिकारी रुहीना तुफ़ैल खान, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं महिला कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

घर में लगी भीषण आग, बाहर खड़ी कार और 5 बाइक राख

दुर्ग। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र के विद्युत नगर के एक घर में भीषण आग लग गई। आग से घर के बाहर खड़ी एक चार पहिया और 5 दो पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। विद्युत नगर निवासी कमला देवांगन के मकान देर रात घर के अंदर खड़ी टाटा नेक्सॉन में अज्ञात कारण से आग लग गई आग से भीषण रूप ले लिया और आसपास खड़ी और 5 दो पहिया वाहन समेत चार एसी को अपने चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलने पर जिला दमकल विभाग को टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले घर के अंदर रखे 7 गैस सिलेंडर को बाहर निकला गया। जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखो का नुकसान की अनुमान जाती जा रही है। पुलगांव थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर घटनास्थल के लिए एक टीम रवाना किया गया।

जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस का दुरुपयोग

कोंडागांव। कोंडागांव जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मरीजों को लाने-ले जाने के बजाय इस एम्बुलेंस का उपयोग जिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. सी.के. ठाकुर अपने निजी कार्यों के लिए कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब वे समय-सीमा की बैठक में शामिल होने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, वह भी एम्बुलेंस से। कोंडागांव जिला कलेक्ट्रेट में जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस घंटों से खड़ी है। मरीजों की सेवा के लिए दी गई यह एम्बुलेंस यहां इसलिए खड़ी नहीं है क्योंकि कोई आपातकालीन स्थिति है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. सी.के. ठाकुर इसे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मंगलवार सुबह जब जिला कलेक्ट्रेट में समय-सीमा की बैठक थी, तब अधीक्षक इस एम्बुलेंस से पहुंचे और इसे वहीं खड़ा कर बैठक में चले गए। घंटों तक यह एम्बुलेंस उनका इंतजार करती रही, जबकि जिले में मरीजों के लिए एम्बुलेंस की कमी बनी हुई है।

थाना परिसर में जमकर हुई मारपीट, चले लात घूंसे

कोरबा। कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड में अशरफ मेमन और गुलाम शेखानी के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद हड़कप मच गया। बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दोनों के ही आदमी मौके पर पहुंचे और विवाद और बढ़ गया। बस स्टैंड पर हुए विवाद के बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली थाना शिकायत दर्ज करने पहुंचे। जहां कोतवाली थाना परिसर पर दोनों के बीच फिर से मारपीट हो गई। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे और मुक्का चलाने लगे। दोनों के बीच मारपीट और गली गलौज सुनकर थाने के अंदर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी दौड़कर बाहर पहुंचे। लेकिन तब तक दोनों खून से लहूलुहान हो चुके थे। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष के लोग कोतवाली थाना परिसर पर पहुंच गए और भीड़ लग गई। पुलिस ने किसी तरह सभी को कोतवाली थाना से बाहर भगाया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर ही रहे थे कि फिर से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। जहां पुलिस ने दोनों की शिकायत पर तत्काल मुलायजा के लिए अस्पताल रवाना किया गया।

बस्तर जिले में तैनात आरक्षक ने किया सुसाइड

जगदलपुर। बस्तर जिले के बड़ाजी थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली है, घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुँच जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि बड़ाजी थाने में पदस्थ आरक्षक नवलेश कश्यप 25 वर्ष ने मंगलवार की सुबह अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित तकरागुड़ा के जंगल में आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक आरक्षक पहले डीआरजी में था, उसके बाद उसकी पदस्थापना बड़ाजी थाने में कर दिया गया। वहीं मृतक लोहंडीगुड़ा का ही निवासी बताया जा रहा है। मृतक आरक्षक कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। लेकिन कारणों का पता नही चल पाया है। वहीं इस संबंध में उनके परिजनों से लेकर दोस्तों तक को इस मामले की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की जानकारी लगते ही एक टीम को घटनास्थल भेज दिया गया। जहां शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है।

बस्तर पंडुम का आज से भव्य आगाज, सजेगा लोकसंस्कृति का मंच

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की अनूठी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से ''बस्तर पंडुम 2025'' का भव्य आयोजन 12 मार्च से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप इस आयोजन के माध्यम से बस्तर संभाग की समृद्ध लोककला, रीति-रिवाज, पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह महोत्सव न केवल बस्तर के प्रतिभाशाली कलाकारों को एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि उनकी कला को नई पहचान और प्रोत्साहन भी देगा।

7 प्रमुख विधाओं पर केंद्रित होगा आयोजन

''बस्तर पंडुम 2025'' में जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, पारंपरिक वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प-चित्रकला और जनजातीय व्यंजन एवं पारंपरिक पेय से जुड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये स्पर्धाएं तीन चरणों में संपन्न होंगी। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता 12 से 20 मार्च, जिला स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 23 मार्च, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता दंतेवाड़ा में 1 से 3 अप्रैल तक सम्पन्न होगी। प्रत्येक स्तर पर प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

बस्तर की लोककला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन

इस महोत्सव में बस्तर की पारंपरिक नृत्य-शैली, गीत, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण और पारंपरिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन होगा। प्रतियोगियों के प्रदर्शन को मौलिकता, पारंपरिकता और प्रस्तुति के आधार पर अंक दिए जाएंगे। आयोजन में समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं के चयन के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ आदिवासी समाज के वरिष्ठ मुखिया, पुजारी और अनुभवी कलाकार शामिल रहेंगे। इससे प्रतियोगिता में पारदर्शिता बनी रहेगी और पारंपरिक लोककला को न्याय मिलेगा।

बस्तर की संस्कृति को सहेजने का सुनहरा अवसर

''बस्तर पंडुम 2025'' सिर्फ एक महोत्सव नहीं, बल्कि बस्तर की गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने तथा उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास है। यह आयोजन बस्तर के कलाकारों के लिए सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपनी कला और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ एक नई पहचान भी बना सकेंगे। छत्तीसगढ़ की अनमोल विरासत को जीवंत रखने का यह महोत्सव प्रत्येक नागरिक के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहेगा।

चिरायु टीम के प्रयास ने अपेक्षा को दी नई जिंदगी

महासमुंद। ग्राम झालखम्हरिया की 8 साल की नन्ही अपेक्षा साहू की जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई, जहाँ हर पल मौत की परछाईं उसका पीछा कर रही थी। उसके मासूम बचपन पर ब्लड कैंसर के एक दुर्लभ प्रकार एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया (एपीएमएल) ने गहरा असर डाला। महीनों से चला आ रहा बुखार, शरीर पर उभरते चकत्ते और पीलापन किसी गंभीर खतरे का संकेत दे रहे थे। जब स्वास्थ्य विभाग की चिरायु टीम को उसकी हालत का पता चला, तो बिना देरी किए उसे एम्स रायपुर ले जाया गया, जहाँ विस्तृत जांच के बाद उसकी बीमारी की पुष्टि हुई।

इलाज की शुरुआत कीमोथेरेपी से हुई, लेकिन यह जितनी जरूरी थी, उतनी ही खतरनाक भी साबित हुई। पहली ही खुराक के बाद उसके शरीर ने गंभीर प्रतिक्रिया दी, अचानक दौरे पडऩे लगे, मस्तिष्क में रक्तस्त्राव (सीवीए) हो गया, और उसका बायाँ हिस्सा अर्ध-पक्षाघात (हेमिप्लेगिया) से प्रभावित हो गया। यह सब देखकर उसके माता-पिता का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और उन्होंने इलाज बीच में ही रोकने का फैसला कर लिया।

लेकिन यही वह क्षण था जब चिरायु टीम ने उम्मीद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने माता-पिता को समझाया कि यह लड़ाई अधूरी छोड़ देना ही असली हार होगी। उनकी काउंसलिंग और हौसले के चलते अपेक्षा का इलाज दोबारा शुरू हुआ। उसे बाल्को मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने 7 खुराक कीमोथेरेपी पूरी की। दर्द और तकलीफ के बावजूद, उसकी मासूम आँखों में जिंदा रहने की चमक बनी रही। धीरे-धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, और हर गुजरते दिन के साथ वह इस जानलेवा बीमारी पर विजय पाने की ओर बढ़ती गई। ऐसे कठिन समय में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी कारगर साबित हुई। सितंबर 2024 में, जब उसने अपनी आखिरी कीमोथेरेपी पूरी की, तो यह सिर्फ एक इलाज का अंत नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब वह सिर्फ दवाइयाँ ले रही है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने माता कौशल्या की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के ग्राम चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में दर्शन व पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री साय ने माता कौशल्या एवं प्रभु श्रीराम के समक्ष नमन करते हुए राज्य की प्रगति, जनता की मंगलकामना और सामाजिक समरसता की प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित वैद्यराज सुषेण मंदिर और श्री दशरथ दरबार के भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने माता कौशल्या मंदिर परिसर में स्थित जलसेन सरोवर में कछुओं को दाना खिलाया और मंदिर परिसर के रखरखाव व सौंदर्यीकरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। इस अवसर पर माता कौशल्या जन्मभूमि सेवा संस्थान के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को माता कौशल्या और प्रभु श्रीराम की प्रतिमा का छायाचित्र भेंट किया।

चिमनानी ने बैज से पूछा क्या वे 33 विधायकों को सवाल नहीं पूछने पर करेंगे निष्कासित

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और कांग्रेस संगठन से पूछा है कि क्या वे अपने 33 विधायकों को सवाल न पूछने पर कांग्रेस से निष्कासित करने जा रहे है? भूपेश बार - बार इस बयान को दोहरा रहे है और साबित कर रहे है कि कांग्रेस के केवल 2 ही विधायक सवाल पूछते है? नेता प्रतिपक्ष भी नहीं पूछते? इस हिसाब से तो चरण दास महंत सहित सभी 33 कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस से निष्कासित कर देना चाहिए?

कोरबा निगम सभापति चुनाव जांच के लिए बनी समिति

रायपुर। कोरबा नगर पालिक निगम में सभापति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पार्टी प्रत्याशी की हुई हार को प्रदेश भाजपा ने काफी गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अनुशंसा पर एक तीन सदस्यीय जांच समिति बनायी गई है जिसमें वरिष्ठ नेता गौरीशंकर अग्रवाल,रजनीश सिंह व श्रीनिवास मद्दी को सदस्य बनाया गया है। समिति सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

पुरानी नगर निगम बिल्डिंग के खाली परिसर में लगी आग

रायपुर। मालवीय रोड स्थित पुरानी नगर निगम बिल्डिंग में अचानक आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई। यह घटना गोलबाजार थाना क्षेत्र में हुई, जिससे बाजार में मौजूद दुकानदार और स्थानीय लोग काफी परेशान हो गए। होली त्यौहार के चलते वैसे ही इस बाजार क्षेत्र में भीड़भाड़ थी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ज़मीन पर फेंके गए कचरे में आग लगी हो, जो तेज हवा और गर्मी के कारण फैल गई। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल की गाडियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

चेंबर चुनाव : नाम निर्देशन शुल्क प्रदेश पद के लिये 31000 व जिला पद हेतु 15000

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवराज भंसाली के हस्ताक्षरयुक्त चेम्बर चुनाव-2025 के अंतिम मतदाता 27480 की सूची का प्रकाशन सोमवार को चेम्बर कार्यालय चै.देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारीगण प्रकाशचंद गोलछा, बालकृष्ण दानी, रमेश गांधी, महावीर तालेड़ा, अनिल कुचेरिया,संजय देशमुख, एच.एस.कर, एस.एम.रावते प्रमुख रूप से उपस्थित थे। निर्वाचन अधिकारी श्री गोलछा ने बताया कि चेम्बर कार्यकारिणी की बैठक 23 जुलाई 2024 में स्वीकृत सदस्यों को मत देने एवं 4 वर्ष पुराने सदस्यों को चुनाव लड़ने की पात्रता होगी, जिसके अंतर्गत सदस्यता क्रमांक 00001 से 35339 तक के सदस्यों को चुनाव लड़ने की पात्रता एवं सदस्यता क्रमांक 00001 से 46189 तक के सदस्यों को चुनाव में मत देने की पात्रता होगी। मतदाता चेम्बर के वेबसाइट www.cgchamber.org में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चेम्बर चुनाव में प्रदेश पद-अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष हेतु नाम निर्देशन शुल्क रूपये 31000 एवं जिला पद- उपाध्यक्ष एवं मंत्री हेतु 15000 रुपये निर्धारित किया गया।

बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को कलेक्टर ने रोका, दी समझाइश

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे दोपहिया वाहन चालकों को रोककर उन्हें समझाइश दी और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने बिना हेलमेट पहने, बिना जरूरी कागजात के वाहन चला रहे और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिबंधित जगह पर गाड़ी चला रहे लोगों को रोककर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने दोपहिया चालकों को बताया कि हेलमेट पहनना, वाहन के सभी वैध दस्तावेज रखना और नियमों का पालन करना उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना कागजात के वाहन चलाना कानूनी अपराध है और दुर्घटना की स्थिति में इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने सभी वाहन चालकों को रेड लाइट जंप न करने, सही लेन में वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग से बचने की सलाह दी।

ईडी की गाड़ी में हमला का मामला, सन्नी अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी के बाद ईडी की गाड़ी को रोकने और पथराव करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दुर्ग पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम के एक वाहन को रोकने और पथराव करने की घटना में एफआईआर दर्ज की है। यह टीम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ एक मामले में उनके आवास की तलाशी लेने गई थी। सोमवार रात निजी वाहन के चालक ने उक्त जिले के पुरानी भिलाई थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

सन्नी अग्रवाल समेत 15 से 20 लोगों के खिलाफ पुरानी भिलाई पुलिस ने ईडी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्यवाही के बाद वापसी के समय ईडी की इनोवा गाड़ी में सन्नी अग्रवाल ने पथराव किया था।

ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत भिलाई के मानसरोवर कॉलोनी में बघेल के आवास और दुर्ग में 13 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार, तलाशी करीब आठ घंटे तक चली, जिसके दौरान ईडी ने करीब 30 लाख रुपये नकद और कुछ दस्तावेज जब्त किए। ड्राइवर ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि सोमवार को शाम करीब साढ़े चार बजे बघेल के घर से निकलते समय करीब 15-20 प्रदर्शनकारियों ने चार पहिया वाहन को रोक लिया और कुछ लोग बोनट पर चढ़ गए। एफआईआर में कहा गया है कि किसी ने पत्थर भी फेंका जो वाहन के आगे के शीशे पर लगा। पुलिस ने दंगा फैलाने [191(2)], गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने (190), स्वेच्छा से सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने (221), सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (132) और गलत तरीके से रोकने [126(2)] और भिलाई निवासी सनी अग्रवाल और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति विनाश कानून की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान भूपेश बघेल घर पर मौजूद थे। बाद में उन्होंने ईडी की छापेमारी के मकसद पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस ने कहा कि बघेल के खिलाफ छापेमारी उस दिन सुर्खियों को मैनेज करने की साजिश थी, जब संसद का बजट सत्र फिर से शुरू हुआ और सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ा। चैतन्य बघेल को रायपुर में ईडी कार्यालय में मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी के अनुसार, मध्य भारतीय राज्य में कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का शासन था। संघीय जांच एजेंसी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय से भर गईं।

भूपेश बघेल के बेटे को ईडी का समन, छापेमारी के बाद अब शराब घोटाले में होगी पूछताछ

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में 15 मार्च को तलब किया है। जूनियर बघेल को संघीय एजेंसी के रायपुर कार्यालय में तलब किया गया है। यह तब हुआ जब ईडी ने दुर्ग जिले में भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों सहित 14 ठिकानों पर छापेमारी की। घंटों चली छापेमारी के दौरान, संघीय एजेंसी- सीआरपीएफ की एक टीम के साथ - कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दस्तावेज और लगभग 30 लाख रुपये जब्त किए।

तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए। चैतन्य के अलावा उनके कथित करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ ??पप्पू बंसल और अन्य के परिसरों की भी तलाशी ली गई। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी सुबह करीब सात बजे शुरू हुई और ईडी के तलाशी दल के साथ सीआरपीएफ का सुरक्षा दल भी था। उन्होंने कहा कि चैतन्य बघेल अपने पिता के साथ भिलाई में रहते हैं, इसलिये उस परिसर पर भी छापेमारी की गयी।

शीर्ष अदालत ने 2024 में इस मामले में ईडी की पहली ईसीआईआर (प्राथमिकी) खारिज कर दी थी, जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी। तब ईडी ने उसके द्वारा जुटाये गये सबूतों के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को नयी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और फिर उसने खुद नया मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू/एसीबी ने पिछले साल 17 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी तथा लखमा और पूर्व सचिव विवेक धंड समेत 70 व्यक्तियों एवं कंपनियों को नामजद किया था। उससे करीब एक माह पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराया था।

मुख्यमंत्री साय के बारे में कुछ भी बोलने से पहले बघेल हजार बार सोचें : कश्यप

- **आदिवासी कवासी लखमा के कंधे पर बन्दूक रखकर भूपेश बघेल ने अपने घोटालों की गोली चलाई, वह भूपेश बघेल की आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचायक**

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को प्रदेश के पहले आदिवासी सौम्य और सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हजार बार सोचना चाहिए। वन व सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश हमेशा से आदिवासी विरोधी रहे हैं। उन्हें यह पच ही नहीं रहा है कि कोई आदिवासी भी प्रदेश की कमान सम्भाल सकता है।

कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय प्रदेश ही नहीं, बल्कि समूचे देश के सबसे अनुभवी आदिवासी नेता हैं। उनका अनुभव और राजनीतिक करियर भी भूपेश बघेल से कई गुना बड़ा है। एक बार केंद्रीय मंत्री, दो बार विधायक, तीन बार प्रदेश अध्यक्ष, चार बार सांसद और अब प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप मेंश्री साय के कार्यकाल की देशभर में सराहना हो रही है। श्री कश्यप ने कहा कि श्री साय के नेतृत्व में आज नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी पूरे करने का असर दिखा, समूचे देश में सौम्य सरल लेकिन कड़े निर्णय लेने वाले नेता के रूप में विष्णुदेव साय की पहचान है।

उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को यह समझना चाहिये कि बड़बोलेपन से राजनीति नहीं चलती। अनावश्यक बयानबाजी को छत्तीसगढ़ की सहज-सरल जनता कितना नापसंद करती है, वह भूपेश बघेल ने स्वयं अनुभव किया होगा। श्री कश्यप ने कहा कि जिस तरह एक सरल आदिवासी कवासी लखमा के कंधे पर बन्दूक रखकर भूपेश बघेल ने अपने घोटालों की गोली चलाई, जैसे सारी मलाई चट कर आदिवासी विधायक लखमा के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है, यह भूपेश बघेल की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। कश्यप ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वे घोटालों के आरोपों का सामना न्यायिक प्रक्रिया द्वारा करें। जिस संविधान को बचाने की बड़ी-बड़ी बात कांग्रेस करती है, उसी संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएँ जाँच कर रही है। इसी संविधान ने देश के वंचितों और आदिवासियों को अधिकार दिए हैं, भूपेश बघेल का संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना संविधान विरोधी कृत्य भी है। श्री कश्यप ने कहा कि बघेल संविधान का सम्मान करें, संवैधानिक पद्धति से चुनकर आए प्रतिनिधियों का भी अपमान करने का भूपेश बघेल को कोई अधिकार नहीं है। चोरी पकड़ी जाने पर बौखलाहट से काम नहीं चलता है।

धान खरीदी मामले पर विस में हंगामा

- **खाद्य मंत्री बोले जीतना किसानों से धान आया, उतना खरीदा गया**

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान उठाव के अतिरिक्त धान-चावल के इस्तेमाल का सवाल किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी और जीतने किसानों ने धान मंडी तक लाया था उतना ही धान खरीदा गया है।

बघेल के अपने प्रश्न की शुरुआत खरीफ वर्ष 2024- 25 में केंद्रीय पुल में धान उठाव और चावल जमा करने से की। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि 69.72 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जिसके एवज में अब तक 9 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया गया हैं। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने संजारी बालोद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 22 लाख 500.48 टन धान खऱीदी की गई है। संजारी बालोद में 2024-25 में धान खऱीदी का कितना लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित नहीं बल्कि अनुमानित होता है। इस पर कसंगीता सिन्हा ने सवाल किया कि रकबा से कम खऱीदी क्यों हुई है। मंत्री बघेल ने कहा जीतना किसानों से धान आया, उतना खरीदा गया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि पिछली सरकार जो व्यवस्था करती थी, वही यह सरकार भी करेगी।

नवा रायपुर के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने हेतु बैठक का आयोजन

रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत नवा रायपुर के गांव को मॉडल गांव बनाने हेतु नवा रायपुर में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार नवा रायपुर के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव बनान हेतु मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एनआरडीए, यूनिसेफ़, वॉटर एड, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (हृड्ड्यस्) कलिंगा यूनिवर्सिटी दावडा यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अभनपुर प्रतिभाग किया गया।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सभी राज्य सलाहकारों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, बैठक की संचालन श्रीमती अभिलाषा आनंद द्वारा किया गया । जिला समन्वयक, स्वछ भारत मिशन ग्रामीण, रायपुर द्वारा संबन्धित ग्राम पंचायतों किए गए कार्य के संबंध में प्रस्तुति करण किया गया। बैठक में शासन के मनसा अनुरूप नवा रायपुर के गांव को स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल बनाने में सभी की सहयोग हेतु चर्चा किया गया। चयनित पंचायतों में निरतंर सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, प्रचार-प्रसार गतिविधि, नुक्कड नाटक, स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षण , हेल्थ कैंप, स्कुल रैली, शौचालय के निरतंर उपयोग, श्रमदान, स्वच्छता अभियान का आयोजन कर गांव को स्वच्छ-सुंदर गांव बनाने हेतु सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता के संबंधित विभिन्न गतिवधियों के आयोजन से संबंधित चर्चा की गई। मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा आगामी 2 माह में इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु कार्य योजना निर्माण करने हेतु अनुरोध किया गया।

पलामु एनकाउंटर में गैंगस्टर अमन साव ढेर

रायपुर-रांची। कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को रिमांड पर लेकर कड़ी सुरक्षा के साथ झारखंड लेकर जा रही झारखंड पुलिस की गाड़ी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। एकाएक हुए इस हमले में पुलिस ने मोर्चा सम्हालते हुए भाग रहे अमन साव का एनकाउंटर कर दिया। इस हमले में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया जिसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर अमन को 14 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कारोबारी पर फायरिंग मामले में रायपुर लाया गया था। इसके बाद से वह महीनों से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद था।महीनों से रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव पर जेल से गैंग ऑपरेट करने का आरोप था। पलामू पुलिस कप्तान रीष्मा रमेशन ने इस एनकाउंटर में अमन साव के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना मंगलवार की सुबह 9ः15 बजे की है. एनआइए की टीम को एक मामले में अपराधी अमन साव से पूछताछ करनी थी इसलिए झारखंड पुलिस अमन साव को सोमवार की देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच रिमांड में लेकर रायपुर जेल से झारखंड ला रही थी। इसी दौरान चैनपुर-रामगढ़ मार्ग पर अंहारी ढोड़ा के समीप अपराधियों ने पुलिस की स्कॉर्पियो पर बम फेंककर हमला कर दिया,इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गयी।

पलामू पुलिस कप्तान ने बताया कि अपराधियों ने पहले वाहन पर बम फेंका और इसके बाद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। बताया जाता है कि इस बीच स्कॉर्पियो में बैठा अपराधी अमन साव ने हवलदार राकेश कुमार की इंसास राइफल छीनकर उसके सिर पर तान दी और मौके का फायदा उठा कर भागने लगा। इसी क्रम में पुलिस व अपराधियों के बीच हुए एनकाउंटर में अपराधी अमन साव ढेर हो गया।

अपराधियों की गोलीबारी से हवलदार राकेश कुमार के जांघ में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है. पुलिस को भारी पड़ता देख अपराधी भाग निकले। घटना के बाद पुलिस सर्च अभियान चला रही है। पुलिस ने घटना स्थल से दो जिंदा बम भी बरामद किया है। पुलिस कप्तान के मुताबिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपराधी अमन साव के शव को घटनास्थल से उठाया जायेगा। कुख्यात अपराधी अमन साव झारखंड-बिहार के लिए आतंक का पर्याय बन गया था। वह पुलिस प्रशासन के लिए सिर दर्द बना हुआ था। उसके आतंक से बड़े व्यवसायी, संवेदक और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े अधिकारी भयभीत रहते थे।

अमन साव के गिरोह ने पलामू में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। उसने मेदिनीनगर केंद्रीय जेल के जेलर को भी धमकी दी थी। पलामू में थर्ड रेलवे लाइन निर्माण कार्य, फोरलेन सड़क निर्माण सहित कई बड़ी योजनाओं में कार्य कर रहे संवेदकों को धमकाया था। साइट पर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था।

लाखों महिलाओं को नहीं मिल रहा महतारी वंदन योजना का लाभ : महंत

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का बड़ा आरोप, कहा- यह अन्याय है

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत ने महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि महतारी वंदन योजना के नाम से चुनाव जीते हैं, लेकिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। एक ही क्षेत्र में 4000 महिलाओं को लाभ नहीं मिला है। पूरे प्रदेश में लाखों महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

भूपेश बघेल के निवास पर छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों से बदसलूकी, गाड़ियों में तोड़फोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर डॉ। महंत ने कहा कि गिरफ्तारी हो रही है, तो सामान्य व्यवस्था है। हम आक्रोश व्यक्त करेंगे, हमने आक्रोश व्यक्त किया। हमने गाड़ी में धक्का-मुक्की की। यह सामान्य आक्रोश है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करना मानसिक स्थिति को दर्शाता है।

मंत्री राजवाड़े ने गिनाए गई कारण

राज्य सरकार की महत्वकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ एक भी किश्त 3971 महिलाओं को नहीं प्राप्त हुआ है, इसके कई प्रमुख कारण है। यह जानकारी कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिए। पुराना पैसा देने से इंकार किए जाने पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

प्रश्न काल में कांग्रेस के विक्रम मंडावी ने पूछा कि कितनी महिलाओं को वंदन योजना की एक किश्त की राशि नहीं मिली है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ऐसी महिलाओं की संख्या 3971 है। मंत्री ने बताया कि इसके कई कारण है जैसे आधार कार्ड की सीडिंग न होना, आधार नंबर असक्रिय होना, खाते पर रोक, खाते बंद होना, खाताधारक की मौत व अन्य तकनीकी कारण शामिल हैं। मंडावी ने कहा कि इन 3971 की राशि का एक वर्ष से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या आवेदनों में सुधार कर राशि देंगे? उमेश पटेल ने कहा कि एक वर्ष में सुधार नहीं कर पाए, कब तक करेंगे। इस पर मंत्री राजवाड़े के यह कहते ही कि अब पिछली सरकार पर जवाब दूंगी तो कहेंगे पिछली सरकार में चले जाते हैं, कांग्रेस की सभी महिला विधायक एक साथ विरोध में उठ खड़े हुई और शोर मचाने लगी। विक्रम और उमेश ने 12 अप्राप्त किश्त एक साथ देने की मांग उठाई। मंत्री ने इससे इंकार कर दिया तो विपक्ष के सभी विधायक बहिर्गमन कर सदन से बाहर चले गए।

मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध

रायपुर। शहर के गुढ़ियारी इलाके में स्थानीय लोग नए मोबाइल टावर के लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि मोबाइल टावर लगने से क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मांग की है कि यहां टावर ना लगाया जाए।

पूरा मामला गुढ़ियारी के अशोक नगर का है। जहां मोबाइल टावर को लगाने का कार्य जारी है। इस बीच लोगों ने आज नारेबाजी करते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही मोबाइल टावर को हटाए जाने की मांग की जा रही है।

स्थानीय रहवासी रमाकांत शर्मा ने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र सेवई फेक्ट्री के पास अशोक नगर गुढ़ियारी एपीजे कलाम वार्ड क्रमांक 19 रायपुर में मोबाइल टावर लग रहा है। जबकि यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अगर यहां मोबाइल टॉवर की स्थापना हो जाती है। तो उसके उच्च रेडियेशन से आस-पास का वातावरण खराब हो जायेगा।

वहीं स्थानीय रहवासी कुंदन सिन्हा ने कहा कि घनी आबादी वाला यह पूरा क्षेत्र है। मोबाइल टावर लगाने से बच्चो के साथ-साथ आस-पास के सभी लोगो के मानसिक स्थिती पर भी बुरा प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। उच्च रेडियेशन से मानव स्वास्थ्य में कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। इससे हम सभी भली भांति अवगत है। रेडियेशन की वजह से क्या क्या खतरा मानव शरीर एवं वातावरण में हो सकता है, ये सभी जानते है।

तमिलनाडु में हिंदी विरोध के राजनीतिक कारण

उमेश चतुर्वेदी

हिंदी को लेकर तमिलनाडु की राजनीति का आक्रामक होना कोई नयी बात नहीं है। हिंदी के विरोध में जिस तरह स्टालिन ने रोजाना आधार पर मोर्चा खोल रखा है, वह 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की याद दिला रहा है। संवैधानिक प्रावधानों की वजह से 26 जनवरी, 1965 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर जिम्मेदारी संभालनी थी, जिसके विरोध में सीएन अन्नादुरै की अगुवाई में पूरी द्रविड़ राजनीति उतर आयी थी। तब हिंदी विरोध के मूल में तमिल उपराष्ट्रीयता थी। उसके लिए तब यह साबित करना आसान था कि उस पर हिंदी थोपी जा रही है। परंतु आज हालात बदल चुके हैं। चाहे तमिलनाडु का निवासी हो या फिर उत्तर भारत के किसी हिंदी भाषी क्षेत्र का, उसके हाथ में यदि फोन है, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन है, तो तय है कि उसकी अंगुलियों के नियंत्रण में हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं, दुनियाभर की भाषाएं हैं। इसलिए हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा का विरोध अब दुनिया के किसी भी कोने में पूरी तरह न तो सफल हो सकता है और न ही कोई दीवार उसे रोक सकती है। बेशक तमिलनाडु भाषाई स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है, परंतु वह भी भारत का हिस्सा है। मौजूदा स्थिति में तेजी से विकसित होता राज्य है और उसे अपने उत्पादन केंद्रों के लिए कामगारों की जरूरत है। जिसकी आपूर्ति उत्तर भारत के ही राज्य करते हैं। उसके निजी शैक्षिक केंद्रों के लिए विद्यार्थियों की भी जरूरत है। उत्तर भारत की जो शैक्षिक स्थिति है, उसकी असलियत सबको पता है। इसकी वजह से उत्तर भारतीय छात्रों की आवक भी तमिलनाडु में खूब है। ऐसे में हिंदी विरोध के औचित्य पर ही प्रश्न है, फिर भी स्टालिन विरोध कर रहे हैं तो उसके अपने कारण हैं। संचार और सूचना क्रांति तथा तेज आवागमन के चलते भाषायी स्तर पर तमिलनाडु की स्थिति तीन-चार दशक पहले जैसी नहीं है। वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या भले कम हो, पर उसे समझने और हिंदी में आने वाले सवालों का जवाब देने वालों की तादाद बढ़ी है। हिंदी या कोई अन्य भाषी वैसे भी तमिल संस्कृति को इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तमिल संस्कृति और भाषा दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में से एक है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तमिल लोग अपनी संस्कृति और भाषा से नेह-छोह ही नहीं रखते, उसका शिद्दत से सम्मान भी करते हैं। फिर तमिलनाडु की ऐसी स्थिति नहीं है कि दिल्ली, जालंधर, सूरत, लुधियाना, मुंबई की तरह तमिलनाडु के शहरों में हिंदी भाषियों की बाढ़ आ जायेगी। वैसे जिन जगहों का जिक्र हुआ है, वहां हिंदी भाषियों की बाढ़ होने के बावजूद क्या वहां की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं पर संकट आया। इसका उत्तर न है। होता यह है कि बाहर से आया व्यक्ति स्थानीय संस्कृति और समाज के लिहाज से वहां व्यवहृत भाषा (स्थानीय भाषा) को अपने सामाजिक और सार्वजनिक कामकाज की भाषा बनाता है, वह अपनी बोली-बानी को अपने सीमित समाज और परिवार में ही उपयोग करता है। पता नहीं इन तथ्यों को स्टालिन समझते हैं या नहीं, परंतु वे बार-बार हिंदी पर आरोप लगाते रहते हैं कि वह तमिल संस्कृति को हानि पहुंचायेगी। असल में, तमिलनाडु की राजनीति में पिछली शताब्दी के साठ के दशक से ही स्थानीय द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व बना हुआ है। कभी डीएमके, तो कभी एआइएडीएमके जैसी स्थानीय पार्टियां ही सत्ता की मलाई खाती रही हैं। सही मायने में देखें तो ये महज स्थानीय पार्टियां ही नहीं हैं, बल्कि अपने-अपने हिसाब से तमिल उपराष्ट्रीयता का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तमिल उपराष्ट्रीयता होना बुरी बात नहीं है, परंतु वह राष्ट्रीयता पर हावी नहीं होनी चाहिए। पर कड़वा सच है कि तमिल उपराष्ट्रीयता राष्ट्रीय मूल्यों पर हावी रही हैं। इसी के ही जरिये द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज रही है। परंतु संचार और सूचना क्रांति के दौर में अब तमिल उपराष्ट्रीयता वाली सोच को लगने लगा है कि यदि हिंदी आयी, तो उसके जरिये राष्ट्रीयता की विचारधारा मजबूत होगी। जिसका असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। परिणाम हो सकता है द्रविड़ राजनीति की विदाई। स्टालिन को लगता है कि यदि उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार कर लिया, नयी शिक्षा नीति को राज्य में लागू होने दिया तो जिस स्थानीयता केंद्रित भावना प्रधान राजनीति वह या उनके साथी स्थानीय दल करते हैं, उसका प्रभाव छीनने लगेगा। इससे स्थानीय राजनीति में उनका वर्चस्व कमजोर होगा और हो सकता है कि एक दौर ऐसा आये कि दूसरे राज्यों की तरह यहां भी राष्ट्रीय राजनीति हावी हो जाए।

कुलभूषण को किडनैप करने वाले को किसने ठोक दिया?

अभिनय आकाश

अंधेरी रातो में सुनासन रहो पर, हर जुल्म मिताने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। 90 के दशक में टीनू आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म शहंशाह का किरदार अभिताभ बच्चन ने निभाया था। जब रात के अंधेरे में गुप्त नायक शहंशाह गरीबों की मदद करता है और अपराधियों को चुनचुन कर ठिकाने लगाता है। जिसके खौफ से मुख्तार सिंह जैसा बदमाश अपनी सारी बदमाशी छोड़ भैंसों का तबेला चलाने लगता है। लेकिन अब कुछ ऐसा ही नजारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। शहंशाह का एक इशारा हुआ और हिंदुस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम पहुंच गया। जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत एक खुफिया ऑपरेशन में लगा हुआ है? क्या भारत ने बदला लेने में इजरायल को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर दुनियाभर में कई दिनों से चर्चा चल रही है। पाकिस्तान की पनाह में छिपे हिंदुस्तान के दुश्मनों में दहशत का माहौल है। आतंकी और उनके मददगार अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। शहंशाह के गुमनाम गन मैन भारत में दहशत फैलाने वालों और भारत के खिलाफ साजिश करने वालों का एक एक कर हिसाब कर रहे हैं। ताजा हमले में कुलभूषण जाधव को किडनैप करने वाला आईएसआई एजेंट और तस्कर की हत्या की गई। कैसे हुई शाह मीर की हत्या और अब तक ऐसे कितने लोगों को अज्ञात हमलावर खत्म कर चुका है?

पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव का किडनैपर, ड्रग्स और हथियारों का तस्कर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसएआई का मोहरा मुफ्ती शाह मीर ढेर हो चुका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धर्मगुरु मुफ्ती शाह मीर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीर 7 मार्च की रात केच के तुरवत शहर में नमाज के बाद एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोली मार दी। भारतीय कारोबारी और नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण कराने में मीर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद की थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोली लगने के बाद मीर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मीर मुफ्ती की आड़ में मानव और हथियारों की तस्करी में लिप्त था। वह इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक दल जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम से भी जुड़ा था। पिछले साल मीर पर दो बार जानलेवा हमले किए गए थे।

मीर जमीयत ओलमा-ए-इस्लाम नामक एक इस्लामी कट्टरपंथी सियासी पार्टी का सदस्य था। वह मुफ्ती होने की आड़ में हथियार और मानव तस्कर के रूप में काम करता था। वह आईएसआई का मददगार था। उसके अक्सर पाक के उन आतंकी शिविरों में जाने की भी खबरें मिलती रही हैं, जहां भारत विरोधी योजनाएं तैयार की जाती रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मीर लंबे समय से पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान क्षेत्र की खुफिया जानकारी देता था। मीर को हत्या का डर था, तभी उसने बाहर आना-जाना काफी कम कर दिया था। एक सूत्र ने बताया, %वह पाक सेना को बलूच लड़ाकों के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था। 2023 में तुर्बत में ईशनिंदा में टीचर की हत्या में मीर का ही हाथ था।%

कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। पाक का दावा है कि कुलभूषण भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कर्मचारी हैं और उन्हें जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। 30 मार्च 2016 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कुलभूषण ईरान में कानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहे थे उस दौरान उनका अपहरण कर लिया गया। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव को पाक की जेल में प्रताड़ित किया जाता रहा है। पाक सैन्य कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंक के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे ने 2019 में पाक से कहा था कि वह भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करे और सजा की समीक्षा भी सुनिश्चित करे। इस हाई प्रोफाइल कत्ल के बाद पाकिस्तान की आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी सकते में है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी मुफ्ती मीर की हत्या करने वाले को तलशा रही है। मीर आईएसआई का एक करीबी मोहरा था। एजेंसी के इशारे पर वो एलओसी से सटे लॉन्च पैड पर एक्टिव रहता था। पाकिस्तानी लॉन्च पैड से आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराना उसका काम था। जैश अल-अदल के ईरानी को भी उसके दो बेटों के साथ नवंबर 2020 में तुर्बत में कथित तौर पर आईएसआई ने मार डाला था। संदेह है कि मीर को भी ड्डस्ढ्ढ ने खत्म कराया है। कुछ समय से चल रहे संघर्ष का यह नतीजा माना जा रहा है। इससे पहले कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग से जुड़े एक और शख्स कर्नल हबीब जाहिर पर गोली चल चुकी है। 26 फरवरी को कर्नल हबीब पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की थी। कर्नल हबीब जाहिर भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट था। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन एक एक कर ढेर हो रहे हैं।

आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। पाकिस्तान वैसे तो आतंकियों का सबसे महफूज पनाहगाह है, इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन अब पाकिस्तानी आतंकवादी अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी पर यादों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश कर रहा है। भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक इम्तियाज आलम उर्फ ??बशीर अहमद पीर, पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौत हो जाती है। फिर 26 फरवरी को अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या कर दी। फरवरी में ही पाकिस्तान में एक और कश्मीरी आतंकी की हत्या की खबर आई। इस आतंकी का नाम खालिद राजा बताया गया। खबर तो ये भी है कि इसी डर से दाउद इब्राहिम से लेकर हाफिज सईद ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है। कुछ दिन पहले ही पाक के पूर्व मेजर ने दावा किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ लाहौर में ऑपरेशन कर रही है। हालांकि इसको लेकर कोई पुष्ट जानाकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

एकात्मता के स्वर

श्रीमद्भगवतगीता

श्रीमद्भगवत गीता हमारे धर्मग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल हीरा है। पिण्ड-ब्रह्माण्ड-ज्ञान सहित आत्म विद्या के गूढ़ और पवित्र तत्वों को थोड़े में ही स्पष्ट रीति से समझा देने वाला, उन्हीं तत्त्वों के आधार पर मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ की पहचान करा देने वाला भक्ति और ज्ञान का मेल करा के इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और इसके द्वारा संसार में त्रस्त मनुष्यों को शांति देकर उसे निष्काम कर्तव्य में, आचरण में लगाने वाला गीता के समान बालबोध ग्रंथ संस्कृत की कौन कहे, समस्त संसार के साहित्य में भी नहीं मिल सकता। केवल काव्य की ही दृष्टि से इसकी परीक्षा की जाये तो भी यह ग्रंथ उत्तम काव्यों में गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूढ़ सिद्धांत ऐसी प्रासादिक भाषा में लिखे गये हैं, कि वे बूढ़ों और बच्चों को एक समान सुगम हैं। इसमें ज्ञानयुक्त भक्तिरस भी भरा पड़ा है। जिस ग्रंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् की वाणी से संग्रहीत किया गया है। उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया जाये? गीता के उपदेश के समय भगवान् किस भावभूमि में थे इसका पता इस बात से चलता है कि युद्ध समाप्ति के बाद एक दिन अर्जुन ने कहा तत सर्वं पुरुषव्याघ्र नष्टं में भ्रष्टचेतस:।। मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया (भूल गया) है। अत: वही ज्ञान मुझे फिर बता दीजिए। तो भगवान् श्रीकृष्ण जी कहते हैं न च श्क्यं पुनर्वक्तुमशेषेण धनंजय। धनंजय अब मैं उस उपदेश को ज्यों की त्यों नहीं कह सकता। क्योंकि उस समय योगयुक्तेन तन्मया योगयुक्त होकर मैंने परमात्मत्त्व का वर्णन किया था। इस ग्रंथ में सम्पूर्ण उपनिषदों का सार सात सौ श्लोकों में दिया गया है। गीता के बारे में एक श्लोक प्रचलित है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन:। पार्थो वत्स: सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत् ।। अर्थात् जितने उपनिषद् हैं वे मानो गौएँ हैं, श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुहने वाले (ग्वाला) हैं, बुद्धिमान अर्जुन (उन गौओं को पल्हाने वाला) भोक्ता बछडा (वत्स) है। और जो दूध दुहा गया वही मधुर गीतामृत है। इस गीता का वर्णन व्यास जी ने अपने महाभारत के भीष्मपर्व के पच्चीस से बयालीसवें अध्याय तक किया है। निष्काम कर्म की प्रेरणा देने वाली गीता में चौथे और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग सरल भाषा में बताया गया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के गमन की चर्चा की तो आस्तिक और नास्तिकों का वर्णन भी। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के ज्ञान की भी चर्चा की है। गृहस्थ और संन्यासी के जीवन का स्पष्ट उल्लेख है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

शब्द-वाक्य-विन्यास विलक्षण, अर्थ और भाषा सरहस्य। अद्भुत शैली सुपुराणों की, यही छठा अध्याय प्रशस्य।।

सातवां अध्याय- सर्गो विसर्गो मनवो वंशास्तच्चरितानि च । पुराण-विषया: पञ्च साङ्गोपाङ्गा इहाङ्किता:॥ यद्यपि पुराणों का विषय पुराणों के पड़ने से ही सर्वांश में विदित हो सकता है तथापि विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध, अधिकारी इन चारों अनुबन्धों के निरूपण करने पर ही व्याख्यान की पूर्णता मानी जाती है, एतदर्थ अन्यतम अनुबन्ध विषय के परिज्ञानार्थ इस अध्याय में पुराणों के मुख्य विषयों का भी प्रतिपादिन किया जाता है।

पुराणों के पांच विषय- प्राय: सभी पुराणों में पुराणों के पांच विषय मुख्य माने जाते हैं, अत: साक्षर समाज में नीचे लिखा श्लोक खूब प्रचलित है-

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वन्तराणि च। वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्।। (शुक्रनीति 4।63-64)

अर्थात् - सर्ग (सूक्ष्म तत्त्वों की रचना उनका विकास अपक्षय और तिरोभाव) प्रतिसर्ग (स्थूत्र जगत् की उत्पत्ति स्थिति और उसका संहार) वंश-(ऐतिहासिक व्यक्तियों की वंशपरम्परा) मन्वन्तर-(अभुक घटना का किंवा अमुक व्यक्ति का समय जानने के लिये पौराणिक पद्धति का मन्वात्मक विधान) और वंशानुचरित-(धर्मसंकट के समय न्यायपथ निर्धारण करने में मनुष्य समाज के काम में आने वाले अनेक व्यक्तियों के अनुकरणीय जीवन चरित) ये पांच प्रधान विषय पुराणों में वर्णित हैं।

उपर्युक्त श्लोक ब्रह्माण्डपुराण (1।1।37-38) वायु (4 10-11) मत्स्य, 53।65) कूर्म (1।1।12) शिव (5।1।67) गरुड़ (1। 215। 14) भविष्य (1।2।4.5) वाराह (2 ।4) तथा अमरकोश में भी इसी प्रकार लिखा है।

क्रमश: ...

राजा श्रृगाल जब खुद बन बैठा कृष्ण

आशुतोष गर्ग

एक समय की बात है। श्रीकृष्ण अपने गणों के साथ सुधर्मा-सभा में विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया। उसने पहले श्रीकृष्ण की स्तुति की, फिर विनयपूर्वक बोला, 'प्रभो! वासुदेव श्रृगाल नामक एक मंडलेश्वर राजा है; वह आपकी निंदा करता है और उसने आपके लिए यह संदेश दिया है- 'वैकुंठ में चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भारतवर्ष में मेरा आगमन हुआ है। मैंने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मधु और कैटभ को मारकर सृष्टि की रक्षा की है। मैं ही ब्रह्मा, शिव व?लोकों का पालक विष्णु हूं। मैं प्रकृति से परे निर्गुण नारायण हूं। ऊंचे सिर उठाने वालों को कुचल डालना राजा का परम धर्म है और इस समय मैं पृथ्वी का शासक हूं। मैं चतुर्भुज रूप में शंख-चक्र-गदा-पद्म लेकर सेना सहित युद्ध के लिए उस द्वारका जाऊंगा। मुझसे युद्ध करो; अन्यथा मेरी शरण में आओ। यदि तुम मेरी शरण में नहीं आ जाओगे, तो मैं द्वारका को भस्म कर डालूंगा। मैं अकेला ही क्षण-भर में सेना, पुत्र, गण और बंधु-बांधवों सहित तुम्हें जला डालने में समर्थ हूं।' यह कहकर ब्राह्मण मौन हो गया। उसे सुनकर श्रीकृष्ण ठठाकर हंस पड़े। श्रृगाल के वाग्बाण उनके मन को द्रवित कर रहे थे।

प्रात:काल होते ही श्रीकृष्ण रथ पर सवार हुए और श्रृगाल के पास पहुंच गए। उनके आने का समाचार सुनकर श्रृगाल कृत्रिम-रूप से चार भुजा धारण करके युद्ध के लिए आ गया।

श्रीकृष्ण उसे देखकर मुस्कराए और उससे लौकिक रीति से वार्तालाप किया। वह अचानक श्रीकृष्ण से भयभीत होकर बोला, 'प्रभो! आप सुदर्शन-चक्र से मेरे इस पापी शरीर को नष्ट कर दीजिए।?जय-विजय की तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूं। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मी के शाप से मैं भ्रष्ट हो गया था; मेरा वह समय पूरा हो चुका है। मैं पुन: आपके लोक चला जाऊंगा।'?श्रीकृष्ण बोले, 'श्रृगाल, पहले तुम मुझ पर प्रहार करो; फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा।' तब श्रृगाल ने माधव पर बाणों से वार किया, किंतु वे सब बाण आकाश में विलीन हो गए। फिर श्रृगाल ने अग्नि-शिखा के समान गदा फेंकी, परंतु वह भी श्रीकृष्ण के स्पर्शमात्र से टुकड़े-टुकड़े हो गई। फिर उसने कई अन्य अस्त्र-शस्त्रों से कृष्ण पर वार किया। परंतु उसके सभी अस्त्र-शस्त्र जगदीश्वर कृष्ण के सामने विफल हो गए। अंत में श्रृगाल ने कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, 'प्रभो! आत्मा रूपी आकाश को अस्त्र से बेधा नहीं जा सकता। इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप कर्मों के ईश्वर, ब्रह्मा के भी विधाता, शुभ फलों के दाता, समस्त संपत्तियों के प्रदाता, कर्मों के कारण और उनके खंडन में समर्थ हैं। मैं अपने इस पंच भौतिक नश्वर देह का त्याग करके आपके वैकुंठ के सातवें द्वार पर जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा घर है।'

श्रृगाल के अमृतमयी वचन सुनकर श्रीकृष्ण समरभूमि में स्नेहवश रोने लगे। उनके नेत्रों से गिरे हुए अश्रुबिंदुओं से वहां सहसा 'बिंदुसर' नामक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया; जो तीर्थों में परम श्रेष्ठ है। उसके जल के स्पर्शमात्र से मनुष्य जीवनमुक्त हो जाता है और उसे अपने सात जन्मों के संचित पापों से मुक्ति मिल जाती है।

क्या पड़ोसी बांग्लादेश भी नया नासूर बनने जा रहा है?

विकास मिश्रा

भारत के लिए पाकिस्तान जिस तरह एक नासूर बना हुआ है, क्या बांग्लादेश भी नया नासूर बनने जा रहा है? नासूर अमूमन एक ऐसा घाव होता है जो रह-रह कर बड़ी तकलीफ देता है। अपने शरीर में उपजने वाले नासूर को तो दवाइयों से ठीक किया जा सकता है लेकिन जब अपना पड़ोसी नासूर जैसी तकलीफ देने लगे तो क्या करें? पाकिस्तान के साथ यह सब हम झेल रहे हैं और शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि यह पड़ोसी भी भविष्य में हमें निश्चय ही बहुत तकलीफ देने वाला है।

बांग्लादेश में उथल-पुथल पर वैसे तो पूरी दुनिया की नजर है लेकिन भारत के लिए इस देश के भीतर की हलचल गंभीर मायने रखती है। अभी कई सवाल सामने हैं। लोगों के मन में पहला सवाल तो यही कि अभी वहां सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस क्या पाकिस्तान की मदद से खुद को तानाशाह के रूप में स्थापित करने की मंशा रखते हैं?

यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अंतरिम सरकार संभालने के तत्काल बाद उन्होंने वादा किया था कि बांग्लादेश में शीघ्र ही चुनाव कराए जाएंगे। मगर ऐसी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वे वोट देने की उम्र 17 साल करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में यह चुनाव से दूरी बनाने का बहाना माना जा रहा है।

इस बीच उन्होंने बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान की सेना को न्यौता भी दे दिया। वे यह भूल गए कि इसी पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में भीषण कत्लेआम मचाया था और महिलाओं तथा लड़कियों की अस्मत लूटी थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी सेना को अपने देश में बुलाने का मतलब है कि मोहम्मद यूनुस का कोई न कोई लक्ष्य जरूर है।

यह लक्ष्य तानाशाही के अलावा और क्या हो सकता है? शायद नाहिद इस्लाम को यही शंका हुई जिसके कारण वक्त रहते उन्होंने अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने नेशनल सिटिजन पार्टी का गठन किया है। नाहिद इस्लाम वही छात्र नेता हैं जिन्होंने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस की गोद में सत्ता आ गिरी थी।

नाहिद इस्लाम ने हालांकि अभी तक यूनुस के खिलाफ कुछ बोला नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तानी हस्तक्षेप का डर उन्हें भी सताने लगा है इसलिए वे पहले अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि वे एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं। वे न तो पाकिस्तान के समर्थक हैं और न ही भारत के समर्थक हैं।

वे समानता के आधार पर रिश्ते रखना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि बांग्लादेश की 55 प्रतिशत से ज्यादा की युवा आबादी उनका साथ देगी। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थक नहीं होने की घोषणा करना पाकिस्तानी हुक्मरानों, वहां की सेना और षड्यंत्र करने वाली एजेंसी आईएसआई को रास नहीं आया होगा!

इसलिए यह सवाल है कि वे कितना सफल हो पाएंगे? निश्चय ही उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि बांग्लादेश के सेनाअध्यक्ष वकार-उज-जमा का रुख क्या रहता है? अभी हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि वे आपसी झगड़े बंद करें नहीं तो देश की एकता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी।

इस भाषण का आशय क्या है? उस भाषण के वक्त हालांकि नाहिद इस्लाम ने पार्टी नहीं बनाई थी लेकिन हो सकता है कि उन्हें नई पार्टी के गठन की जानकारी हो और वे नाहिद के साथ जाएं। ऐसा इसलिए कि कोई भी सेना अध्यक्ष किसी दूसरे देश की सेना के इशारों पर नहीं चलना चाहेगा। यूनुस द्वारा पाकिस्तानी सेना को तवज्जो देना उन्हें निश्चय ही अपमानजनक लगा होगा।

बांग्लादेश में एक बड़ी घटना यह हुई है कि प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर मैदान में आ गया है। पिछले शुक्रवार को उसने ढाका में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश में खलीफा राज की स्थापना की जाए। खलीफा राज का मतलब इस्लामिक खलीफा के नेतृत्व वाली सरकार!

पुलिस ने बड़ा मामूली सा विरोध किया और आंसू गैस के गोले छोड़े लेकिन उसके बदले हिज्ब-उत-तहरीर के चरमपंथियों ने हथगोले चलाए। ये वही संगठन है जिसे 2009 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसका लक्ष्य पूरी दुनिया में इस्लामिक शरिया शासन स्थापित करना है। इसे समय-समय पर अरब मुल्कों के अलावा पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने भी प्रतिबंधित कर रखा है।

सवाल यह उठ रहा है कि इस संगठन ने जब प्रदर्शन की घोषणा पहले ही कर दी थी तो फिर पुलिस ने सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाया? वे प्रदर्शन करने या पैम्फलेट बांटने में क्यों सफल हो गए? यूनुस के कार्यकाल में इस चरमपंथी संगठन ने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान भी चलाया है। माना जा रहा है कि इस संगठन को पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों से मदद मिलती है।

इस संगठन ने खुद पर से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हो सकता है कि किसी दिन यूनुस ऐसा कर भी दें। अब सवाल है कि बांग्लादेश में तानाशाह के रूप में मोहम्मद यूनुस कायम रहें या चरमपंथियों का कब्जा हो जाए तो भारत क्या करे? सवाल यह भी है कि नाहिद इस्लाम का रुख भारत के प्रति क्या होगा? या सेना अध्यक्ष वकार-उज-जमा ही तख्तापलट कर दें तो क्या होगा?

हर हाल में भारत के लिए स्थितियां कठिन ही होने वाली हैं क्योंकि ये सभी आंखें तरेर रहे हैं। विभिन्न देशों की कूटनीति में एक कहावत प्रचलित है कि आप सबकुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी यदि उपद्रवी हो जाए तो वह खुद की शांति का तो नाश करता ही है, आपकी शांति को भी नष्ट कर देता है। भारत के लिए ठीक यही हालात हैं। लेकिन दुनिया यह न भूले कि हम चाणक्य की धरती के लोग हैं। कूटनीति हमें भी आती है!

आज का इतिहास

1884 पहली महिला अमेरिकी राज्य कॉलेज की स्थापना मिसिसिपी की गयी।

1894 कोका कोला को पहली बार के लिए बोतलों में बेचना शुरू किया गया।

1912 जूलियट गॉर्डन लो ने लड़कियों के लिए एक युवा संगठन की स्थापना की जो यूएसए के गर्ल स्काउट्स में विकसित हुआ।

1927 जॉन बैरीमोर अभिनीत साहसी फिल्म द थियोडिंग रॉग प्रकाशित की गयी।

1928 कैलिफोर्निया में बने सेंट फ्रांसिस डैम के टूट जाने से आई बाढ़ के कारण 600 लोग मारे गए।

1934 एस्टोनियाई सेना द्वारा समर्थित, कॉन्स्टेंटिन पाट्स ने एरा ऑफ साइलेंस की शुरुआत करते हुए एक तख्तापलट का मंचन किया।

1948 कोस्टा रिकान सिविल युद्ध शुरू हुआ

1952 ब्रिटिश राजनयिक हेस्टिंग्स इस्माय को नाटो के पहले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

1954 फिनलैंड और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की स्थिति खत्म की।

1970 अमेरिका में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गयी।

1993 1993 की मैक्सिको की खाड़ी पर बने सेंचुरी के तूफान, इसकी ऊंचाई पर इसका प्रभाव सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत था।

1995 बर्मिंघम में आइस पेयर्स चैंपियन में राडका कोवारिकोवा और रेने नोवोटनी ने जीत हासिल की।

1995 प्लैटोव और ग्रिट्शुक ने आइस डांस चैंपियनशिप बर्मिंघम जीता।

2008 अमेरिकी वायुसेना ने विश्व के पहले स्टील्थ लड़ाकू विमान एफ़-117 को अपने बेड़े से हटाया।

2008 विश्व की सबसे लम्बी आयु की समझी जाने वाली महिला वारवा सेमेनिकोवा का रूस में 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

2011 भूकंप और सुनामी के बाद, जापान खोज और बचाव प्रयासों में 50,000 आत्मरक्षा बलों के कर्मियों को तैनात करता है।

विदेशी आक्रांताओं के शुभचिंतकों को सनातन भूमि में रहने का हक नहीं

कमलेश पांडे

सनातन भूमि भारतवर्ष, जिसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, आसेतु हिमालय आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया है, में मुस्लिम आक्रमणकारियों और ब्रिटिश आतताई अधिकारियों के महिमामंडन का जो सियासी होड़ जब-तब मची रहती है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल है कि इनसे जुड़े विभिन्न प्रतीक चिन्हों-स्मारकों आदि, इनके नाम पर बसाए गए गांवों-शहरों, नामांकित सड़कों या विभिन्न संस्थानों को मिटा क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सनातन भूमि पर रिसते घाव की मानिन्द हैं।

यक्ष प्रश्न यह भी है कि आज इनकी जरूरत क्या है, किनको है और क्यों है? और यदि है तो फिर ऐसे देशद्रोहियों की यहां जरूरत है? यदि बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे क्रूर मुस्लिम शासकों या जनरल डायर जैसे क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों या फिर ओसामा बिन लादेन, कसाब जैसे क्रूर आतंकवादियों का, पाकिस्तान-बंगलादेश जैसे फिरकापरस्त ताकतों के शुभचिंतक यहां हैं तो भारतीय प्रशासन का यह पहला कर्तव्य है कि राष्ट्रहित में इनकी शिनाख्त करे और इन्हें राष्ट्रीय सीमा से बाहर करे।

यह अहम बात है कि जब तक ये बाहर नहीं हो जाते, तबतक इनको मताधिकार और राष्ट्रीय जनसुविधाओं से वंचित किया जाए। इनके भारतीय पहचान पत्र निरस्त किये जाएं। क्योंकि सुलगता सवाल है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जब कोई नेता या बुद्धिजीवी सिर्फ मजहबी कारणों से जुल्मियों का महिमामंडन करने का दुस्साहस करे, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना भारतीय प्रशासन का पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि इस पवित्र हिन्दू भूमि पर ऐसा करते रहने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है! ऐसे देशद्रोही, सनातन द्रोही तत्वों के खिलाफ भारतीय नेताओं और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस दिशा में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा इनके हौसले बढ़ेंगे।

कहना न होगा कि जब हम इंडिया कहते हैं तो उसका अभिप्राय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, वर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव समेत भारत के उस विशाल भूभाग से लिया जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में सुप्रसिद्ध हिन्दू भूमि है। यदि आप महाभारत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह पूरी दुनिया ही सनातनी थी, देवत्व मिजाजी थी और जो दानव या असुर मिजाजी थे, वो हिंदुओं से अलग होते गए। फिर भी आर्यावर्त में हिंदुत्व का दबदबा हमेशा बना रहा। इसलिए चाहे मुस्लिम आक्रमणकारियों का जत्था रहा हो या ब्रिटिशर्स ईसाइयों की फौज और उससे जुड़े लोग, जो यहां पर विदेशी आक्रमणकारी बनकर आए, यहां के शांतिप्रिय लोगों पर जुल्म ढाए और फिर यहीं रच-बस गए हैं। इन्होंने हथियार के बल पर धर्मांतरण कराया और सनातन मंदिरों उनके संरक्षक रजवाड़ों को नष्ट किया।

चूंकि ये सभी बाहरी आक्रांता हैं, मंगोल या अरब से आये हैं, इसलिए इनकी असली जगह इनके मूल देशों में है, न कि सनातन भूमि में! क्योंकि इनकी सहानुभूति भारत से नहीं, बल्कि उन्हीं मुल्कों से है। हिंदुओं के नाम पर देश विभाजन करके फिर से भारत में फिरकापरस्त सियासत को बढ़ावा देना, वैसे ही संविधान का निर्माण

करवाना कांग्रेस की ऐसी गलती रही है, जिसकी सजा उसे हिन्दू समाज देता आया है। क्योंकि आजादी के बाद मुसलमानों और ईसाइयों को देश से बाहर करवाना, उनसे जुड़ी स्मृतियों को समाप्त करना और भारतीय शासकों, ऋषियों-मुनियों और देवताओं की स्मृतियां कायम करवाना उसका दायित्व था, लेकिन उसने धर्मनिरपेक्षता और गंगा-यमुना संस्कृति के नाम पर हिन्दू समाज को धोखा दिया।

ऐसा इसलिए कि सनातन भूमि, देव भूमि समझी जाती है। यही ऋषियों-मुनियों की तपोभूमि है। यह अहिंसक भूमि है। जबकि मुस्लिमों-ईसाइयों का स्वभाव ही हिंसक है। ये लोग मांसभक्षी हैं और क्रूर भी होते हैं। इनके राजकाज वश, इनके संसर्ग में रहने वाले हिन्दू भी वैसे ही हो गए, जैसे ये हैं। इन्होंने फुट डालो और शासन करो की नीतियों से हिंदुओं में सामाजिक व जातीय दुर्भावना को जन्म दिया है।आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था भले ही ऐसे तत्वों को धर्मनिरपेक्ष कहती है। लेकिन सदियों से इनका जो स्वभाव रहा है, लड़ाई-झगड़े, दंगा-फसाद की जो नियति रही है, उसके दृष्टिगत तो यही कहना उचित रहेगा कि इन्हें या तो खुद को बदलने का अवसर दिया जाए या फिर भारतीय उपमहाद्वीप से निकाल बाहर किया जाए।

बदलते वक्त की मांग है कि सनातन भूमि की नैसर्गिक जरूरतों के मद्देनजर भारतीय संविधान का पुनर्निर्माण हो। इससे पहले कोई इतना मजबूत शासक बने, जो अखण्ड भारत का निर्माण करे। साथ ही आसेतु हिमालय में रच-बस चुके सनातन द्रोहियों को हृदय परिवर्तन, स्वभाव और संस्कार परिवर्तन यानी धर्मपरिवर्तन कर हिंदुओं में शामिल होने का अवसर दे, अन्यथा जिद्दी बनकर अपने धर्म पर अडिग रहने वालों को उसी प्रकार से आसेतु हिमालय यानी भारतीय उपमहाद्वीप से निकाल बाहर करे जैसे कि अमेरिका अपने यहां के अवैध प्रवासियों को कर रहा है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम और ईसाई आदि रह तो रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन यशोगान करते फिरते हैं अरब और ईसाई देशों का। भारतवर्ष पर शासन करने वाले क्रूर शासकों या अधिकारियों का। खासकर सियासत में तो इनका यशोगान करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आज देश में जिस क्रूर बादशाह औरंगजेब, जो अपने पिता और भाइयों का नहीं हुआ, को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं।

ऐसे में औरंगजेब के उस आखिरी खत की चर्चा यहां मुनासिब है, जो खोल देगा उसका महिमामंडन करने वालों का दिमाग। क्योंकि औरंगजेब के उस आखिरी खत का जिक्र इतिहास की किताबों में हुआ है। इसमें औरंगजेब अपने पापों की कहानी खुद कहता है। विवादास्पद मुगल शासक ने अपनी मृत्यु से पहले के पछतावे में अपने किये गुनाहों का जिक्र किया है। प्रख्यात इतिहासकार राम कुमार वर्मा की लिखी किताब %औरंगजेब की आखिरी रात% में उस खत का मजमून दिया गया है। उसे आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि मुंबई के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने औरंगज़ेब का जो महिमामंडन किया है और उस पर विवाद बढ़ा है, उसकी असली हकीकत आप भी जान लें। इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो पाएंगे कि विवादास्पद मुगल शासकों में सबसे बड़ा नाम औरंगजेब का है। जिसने ने गैर-मुसलमानों पर जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीतियां लागू कीं। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। उसने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसने छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दीं और नाखून उखाड़ लिए। इसके शासन काल में भारत में शरियत के आधार पर फतवा-ए-आलमगीरी लागू किया और बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। उसने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों को नष्ट करवाया और लाखों हिंदुओं की हत्या करवाई। इसकी क्रूरता के कारण करीब-करीब पूरे भारतीय उपमहादीप में मुगल साम्राज्य अपना सबसे ज्यादा विस्तार कर पाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी।

कहा जाता है कि मौत से पहले इसको अपने किये गुनाहों पर पछतावा था। औरंगजेब ने अपने बेटों, आजम शाह और काम बख्श को अपने खेद व्यक्त करने के लिए पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उसने अपने पापों और असफलताओं के बारे में जिक्र किया था।

अमेरिका को कृषि उत्पाद के बाजार में प्रवेश नहीं देने में ही भलाई

प्रमोद भार्गव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के लिए कृषि उत्पाद का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। दरअसल भारत की 70 करोड़ से भी अधिक आबादी कृषि, दूध और मछली व अन्य समुद्री उत्पाद पर आश्रित है। इन उत्पादों से जुड़े लोग आत्मनिर्भर रहते हुए अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि भारत सरकार इनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाए रखने की दृष्टि से मुफ्त अनाज, खाद्य सब्सिडी और किसानों को छह हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देती है। भारत की 70 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि और उससे जुड़े उत्पाद हैं। अब अमेरिका इस परिप्रेक्ष्य में भारत पर द्विपक्षीय बातचीत करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तो खुलें ही, उत्पादों पर शुल्क भी कम हो। यदि भारत कोई समझौता करता है तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए दबाव बनाएंगे। यूरोपीय संघ चीज व अन्य दुग्ध उत्पादों पर शुल्क कटौती की इच्छा जता चुका है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत में इन मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता में शामिल करने की बात कही है। किंतु भारत के लिए कृषि में बाहरी दखल एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारे किसान विदेशी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। भारत में

कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक सांस्कृतिक तरीका भी है। इसीलिए भारत के जितने भी पर्व हैं, उनका पंचांग कृषि पद्धति पर ही आधारित है। जबकि अमेरिका व यूरोपीय देश कृषि को मुनाफे का उद्योग मानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 176 अरब डॉलर था, जो उसके कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत है। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खेती और भारी सरकारी सब्सिडी के साथ अमेरिका और अन्य विकसित देश भारत को अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए आकर्षक बाजार के रूप में देखते हैं। जबकि भारत अपने कृषि क्षेत्र को मध्यम से उच्च शुल्क की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संरक्षित किए हुए है ताकि अपने किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। कृषि क्षेत्र को मुक्त बाजार बनाने का मतलब है कि आयात प्रतिबंधों और शुल्कों को कम करना। कृषि को बाहरी सब्सिडी वाले विदेशी आयातों के लिए खोलने का अर्थ होगा सस्ते खाद्य उत्पादों का भारत में आना। यह खुलापन भारतीय किसानों की आय और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।

राजनीति में सब खंजर उठाए घूम रहे हैं

मा. मोहन लाल

2014 के लोकसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति में बड़े बदलाव आ गए हैं। कभी समय हुआ करता था जब देश की राजनीति में कांग्रेस का एकछत्र राज हुआ करता था। समय क्या बदला कि 2014 के बाद कांग्रेस के एक के बाद एक चुनाव में पैर उखड़ते गए। कभी वक्त था कि देश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनीति में वर्चस्व था। वक्त का करिश्मा देखिए कभी भारत की राजनीति में साम्यवादी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का जोर था। कामरेड ए.के. डांगे, ज्योति बसु, कामरेड हरि कृष्णा, सुरजीत और कामरेड प्रकाश कारत की सभी राजनीतिक दलों में पैठ हुआ करती थी। समय क्या गुजरा कि वामपंथी कहीं नजर नहीं आ रहे। कभी समय था केरल, पश्चिमी-बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्य वामपंथियों के हाथों में थे। आज इन राज्यों में ममता बनर्जी और भाजपा शासन चला रहे हैं।

देश की राजनीति लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह के इर्द-गिर्द घूमती थी। आज यादवों का कुनबा या तो बिखर गया है या कोई प्रभु को प्यारा हो गया। दक्षिण भारत की राजनीति में कभी अन्नादुरई, कभी सी. रामचंद्रन, कभी करुणानिधि और कभी जयललिता का डंका गूंजता था। आज स्टालिन दक्षिण की राजनीति को संभाल रहे हैं। कभी आंध्र प्रदेश में फिल्मी अदाकार भारत की राजनीति को आर्ज़षित करते थे तो आज

उन्हीं के दामाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की राजनीति के प्रनेता बन गए हैं। कल जिन्हें नेता अपना राजनीतिक गुरु कहते थे आज वही नेता गुरु की पीठ में छुरा घोंप कर नए नेता बन गए हैं। भारत की राजनीति में कोई किसी का सगा-साथी नहीं। सभी राजनेता अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं। जन सेवा किसी के हृदय में नहीं है। मैं, बस मैं। बाकी जो सत्य और धर्म की राजनीति की बात करेगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। राजनीति में सब खंजर लिए फिर रहे हैं। मैं स्वयं इस महत्वाकांक्षी राजनीति के कारण 16 सालों से हाशिए पर हूं। अपने सामने राजनीति के धुरंधर जनसंघ के संस्थापक, जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय करवाने वाले, 1961 में लोकसभा सदस्य बनने वाले प्रो. बलराज मधोक को 94 वर्ष की आयु में घुट-घुट कर अपनी आंखों के सामने, गुमनामी में मरते देखा।

'जनसंघ' बनाने वाले प्रो. बलराज मधोक को तब पार्टी आकाओं ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। चेले और अपने कहे जाने वाले, दुर्दिनों में एकदम अपने गुरु और राजनेता को छोड़ जाते हैं। वर्तमान राजनीति 'आया राम, गया राम' से प्रभावित हो गई है। राजनीति के 60 सालों में मैंने तो यही देखा है। आपका क्या हुआ, मुझे पता नहीं। आओ थोड़ा आगे बढ़ कर राजनीति के बदलते स्वरूप पर नजर डालें। एक पार्टी और उसके एकछत्र राज का अंत = 50 साल इस देश की राजनीति को कांग्रेस ने अपने अनुसार चलाया। आज वही कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। नेता विहीन कांग्रेस पार्टी। 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस लगातार हार रही है। 2014 के बाद कांग्रेस का स्थान भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है।

लगता नहीं कि कांग्रेस पुन: जागृत होगी। कांग्रेस अब सिर्फ अतीत की बात बन गई है। कई दल तो सुन्न अवस्था में पहुंच गए हैं। पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी 'शिरोमणि अकाली दल' पंजाब में ही हंसी का पात्र बन गई है। महाराष्ट्र में बाला साहिब ठाकरे की 'शिवसेना' को उनके पुत्र उद्धव ठाकरे संभाल ही नहीं सके। बिहार में आर.जे.डी. प्रमुख एक तो बूढ़े हो गए दूसरा मोदी सरकार उन्हें जेल से ही बाहर नहीं आने देती। यू.पी. में समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली में केजरीवाल को भाजपा वालों ने लूट लिया। आज 'आप' के विधायक विधानसभा परिसर में धरना दे रहे हैं। भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का लगातार बढ़ता प्रभाव = 24 जून, 2008 को 748 क्षेत्रीय दलों के चुनाव आयोग ने नाम दर्ज किए। जब भी किसी क्षेत्रीय दल में राजनेताओं को महत्वपूर्ण पद नहीं मिलता, वे एक नया दल बना लेते हैं। क्षेत्रीय दलों में गुटबंदी, भारत की राजनीति के विकास को रोक रही है।

कांग्रेस ने 1998, 1999, 2004, 2009 के लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों से समझौता कर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने भी 1998 के लोकसभा चुनावों में 15 क्षेत्रीय दलों से समझौता किया। 1999 में 25 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। 19 मार्च, 1998 में अटल बिहारी ने 2 राष्ट्रीय और 15 क्षेत्रीय दलों से मिलकर सरकार बनाई। जून 1996 को देवेगौड़ा ने, 21 अप्रैल 1997 में श्री इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर ने क्षेत्रीय दलों से मिलकर प्रधानमंत्री पद हासिल किए। 13 अक्तूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पुन= 23 क्षेत्रीय दलों से मिलकर 'जनतांत्रिक गठबंधन' बनाया। 22 मई 2004 और मई 2009 में मनमोहन सिंह ने 12 क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकारें बनाईं। मोदी ने भी 2014 से 2024 तक अपने सहयोगियों को छोड़ा नहीं। आज राजनीति का धनीकरण हो गया है = बड़े-बड़े साहूकारों को राजनीति की चटक लग गई है। कई धनी व्यक्ति बैंकों का पैसा लूट विदेशों में भाग गए हैं। अंबानी, अडानी की जय-जयकार हो रही है। रोजमर्रा की वस्तुएं गरीब आदमी के हाथ से छूट रही हैं। मध्यम वर्ग सहमा हुआ है। राजनेताओं तक तो साधारण व्यक्ति पहुंच ही नहीं पा रहा । राजनीति अभद्र भाषा, बेबुनियाद आरोपों और गाली देने वाली बन गई है। हां, 2014 के बाद देस में अस्थिरता खत्म हुई है।

मीडिया को निशाना बनाते पश्चिम के नेता

प्रभु चावला

ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था, 'अमेरिका में राष्ट्रपति का रुतबा चार साल के लिए रहता है, लेकिन पत्रकारिता का असर हमेशा-हमेशा के लिए रहता है।' अब अमेरिका में राष्ट्रपति की मजबूत पकड़ मीडिया में दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों तथा उनके संस्थानों को फटकारते, निशाना बनाते और अपमानित करते हैं। दुनियाभर के राजनेता पत्रकारों को दया का पात्र समझने लगे हैं। संपादकों, रिपोर्टरों, मीडिया मालिकों और विचार लेखकों को धनी व प्रभावशाली लोगों की तरफ से मानहानि के मुकदमों का सामना करना पड़ता है। जो सूचना और संवाद उद्योग अब तक सच का खुलासा करके, बगैर भय के रिपोर्टिंग करके या ताकतवर राजनीतिक शहंशाहों से सवाल करके जिंदा रहा, वह अब इश्तहार और प्रिंटिंग प्रेस रिलीज बांटने, पहले से लिखे व संपादित किये गये इंटरव्यू और महत्वपूर्ण विचार पृष्ठों पर राजनेताओं या कॉरपोरेट दुनिया के लोगों द्वारा शीर्ष नेताओं के पक्ष में लिखे जाने वाले छद्म लेखन का माध्यम रह गया है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि फ्री प्रेस के खिलाफ लड़ाई उस देश ने शुरू की है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कसमें खाता है। अपने कामकाज की शैली तथा बातचीत की प्रतिकूल रिपोर्टिंग से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के मीडिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जब सबसे शक्तिशाली तथा लोकतांत्रिक दृष्टि से बेहद समृद्ध देश का राष्ट्रपति हर मंच से पेशेवर पत्रकारों को निशाना बनाता है, तो यह संक्रामक बीमारी का रूप धारण कर लेती है और जंगल की आग की तरह फैलती है। विगत फरवरी में व्हाइट हाउस में टीवी पत्रकारों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई सार्वजनिक झड़प के बाद ट्रंप ने टिप्पणी की, 'फेक न्यूज मीडिया हर बात को तोड़-मरोड़कर पेश करता है- उसका गढ़ा गया झूठ हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है।' उधर उदार यूरोपीय नेता की छवि वाले ओलाफ शुल्ज ने एक आयोजन में मीडिया को चेताया, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है, जहां उससे हिंसा भड़कती है, सोशल मीडिया पर अंकुश लगाया ही जाना चाहिए।'

इस वर्ष की शुरुआत में फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कथित रूप से उन मीडिया संस्थानों को बंद कर देने को कहा, जो उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। मैक्रों दरअसल एक्स की एक पोस्ट पर आगबबूला हो गये थे, जिसमें घरेलू मुद्दों को न सुलझा पाने के कारण उन पर सवाल उठाये गये थे। पिछले साल जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी नेत्री एलिस वाइड्रल ने कहा था, 'मुख्यधारा का मीडिया संभ्रांतों की कठपुतली है- पत्रकार हमें बदनाम करने के लिए सच को तोड़ते-मरोड़ते हैं।' जिस इंग्लैंड को लोकतंत्र का जनक माना जाता है, आश्चर्यजनक रूप से वहां के प्रधानमंत्री भी मीडिया को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हैं। मीडिया पर लगे प्रतिबंध का औचित्य ठहराते हुए कीर स्टारमर ने चेताया, 'हम उन तमाम भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगायेंगे, जो अलगाववाद को हवा देती हैं।' एक ऑनलाइन पोस्ट के आधार पर की गयी गिरफ्तारी पर हंगरी के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने संसद में कहा, 'पूरे पश्चिमी विश्व में हावी राजनेताओं और मीडिया के भ्रष्ट नेटवर्क का सफाया किया जाना चाहिए।' भारत में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रशासनिक और दूसरी एजेंसियों के जरिये पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं।

कभी राजनीतिक वर्ग मीडिया को संरक्षण देता था। ऐसा वह दया दिखाने के लिए नहीं करता था। अपनी नीतियों और संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए राजनेताओं को मीडिया की जरूरत पड़ती थी। कभी शीर्ष कॉरपोरेट व्यक्तित्व तक अगर साख वाले पत्रकारों का पीछा करते थे, तो इसलिए नहीं कि उन्हें नीति निर्माण से जुड़ी जानकारियों की जरूरत होती थी, बल्कि नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए वे ऐसा करते थे। वही मीडिया अब बड़ी तेजी से अपनी वह साख खो रहा है, जिसे उसने काफी लंबे समय में अर्जित किया था। पत्रकार अखबारों में जो कुछ लिखते हैं या प्राइम टाइम के प्रायोजित शो में जो कुछ दिखाते हैं, उन पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कम रह गये हैं। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की प्रसार संख्या 2015 में साढ़े छह लाख थी, जो घटकर तीन लाख से भी कम रह गयी है। दस वर्ष में उसकी प्रसार संख्या 54 फीसदी घटी है। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' के 40 फीसदी पाठकों ने उसका साथ छोड़ दिया है। 'द वाशिंगटन पोस्ट' की प्रसार संख्या 2015 में 4 ।30 लाख थी, जो 2023 में घटकर 1 ।25 लाख रह गयी।

इंग्लैंड, यूरोप और जापान में भी मीडिया को ऐसे ही दबावों का सामना करना पड़ रहा है। एक दशक पहले जिस 'द डेली मेल' की प्रसार संख्या 15 लाख थी, वह आज सात लाख में सिमट गयी है। 'टाइम' और 'द इकोनोमिस्ट', जैसी पत्रिकाओं को कभी राजनीति और अर्थनीति की सबसे प्रामाणिक पत्रिकाओं में माना जाता था। पर ये भी तेजी से पाठक खो रही हैं। जहां 'टाइम' की प्रसार संख्या में 45 प्रतिशत की कमी आयी है, वहीं 'द इकोनोमिस्ट' की प्रसार संख्या 35 फीसदी घट गयी है। भारत में मीडिया से जुड़े प्रकाशन ढलान पर हैं। सिर्फ यही नहीं कि सभी अखबारों की कुल प्रसार संख्या में भारी गिरावट आयी है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों से चालित और संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ जाने से अखबारों के राजस्व में भी 50 प्रतिशत से अधिक कमी आयी है। ज्यादातर लोकप्रिय और प्रतिष्ठित पत्रिकाएं आज या तो लुप्त हो चुकी हैं या इनके बंद हो जाने के आसार हैं।

अब सत्तारूढ़ संभ्रांतों को अपने संदेश प्रसारित करने के लिए दूसरे प्रसार माध्यम मिल गये हैं। उन्हें विरासत वाले मीडिया माध्यमों की जरूरत नहीं है। अपनी प्रशंसा में चूर ये राजनेता नये तरह के उन सोशल इंफ्लूएंसर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा बनाना है। सत्ता प्रमुख अपने कॉरपोरेट साथियों को मौजूदा मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीद लेने या नया प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि सत्तारूढ़ पार्टियों का अच्छे से हितपोषण हो सके। आंकड़ा बताता है कि पारंपरिक ब्रिटिश मीडिया का राजस्व 2007 का चौथाई हिस्सा रह गया है। भारतीय मीडिया में भी विज्ञापनों पर खर्च चूंकि सोशल और डिजिटल मीडिया में शिफ्ट होता गया है, ऐसे में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राज्य और केंद्र सरकारों के फंड पर दयनीय रूप से निर्भर हैं। अलबत्ता मीडिया की बदहाली का कारण खराब अर्थशास्त्र है। गले में फंदा डालने का काम मीडिया ने खुद किया है। उसे याद रखना चाहिए = 'अगर सभी सुर्खियां एक जैसी हैं, तो यह खबर नहीं, मुफ्त का विज्ञापन है।'

स्टालिन का हिन्दी विरोध मगर भ्रष्टाचार पर चुप्पी

योगेन्द्र योगी

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। इसके बावजूद कि पूरे अमरीका में ज्यादातर अंग्रेजी ही बोली जाती है। ट्रम्प के अनुसार, यह आदेश राष्ट्रीय एकता, सांझा संस्कृति और सरकारी कार्यों में समरसता लाने में मदद करेगा। अमरीका जैसी सुपर पावर की एक आधिकारिक भाषा हो सकती है पर भारत में ऐसा करना आसान नहीं है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार सिर्फ क्षुद्र स्वार्थों और वोट बैंक की खातिर हिन्दी का विरोध कर रही है, जबकि देश के ज्यादातर राज्यों में हिन्दी न सिर्फ आधिकारिक भाषा है बल्कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को देश को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार के कैंसर की परवाह नहीं, पर देश की एकता, समरसता और अखंडता के लिए जरूरी हिन्दी भाषा की केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय नीति का जम कर विरोध कर रहे हैं। स्टालिन जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे लगता है कि तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं होकर कोई अलग देश है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं करेगी, चाहे केंद्र सरकार इसके बदले 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ही क्यों न दे। स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली 2,000 करोड़ रुपए की राशि रोकने की धमकी दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार राजनीतिक लाभ के लिए हिंदी थोपने का फर्जी नैरेटिव बना रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जितना विरोध तमिलनाडु की स्टालिन सरकार कर रही है, उतना देश के किसी अन्य राज्य ने नहीं किया। यहां तक कि बात-बात पर केंद्र की भाजपा सरकार से टकराने को तैयार रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर मुखर नहीं दिखीं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1948-49 में डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले आयोग ने हिंदी को केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बनाने की सिफारिश की थी। आयोग की सिफारिश थी कि सरकार के प्रशासनिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कामकाज अंग्रेजी में किए जाएं। इस आयोग ने कहा था कि प्रदेशों का सरकारी कामकाज क्षेत्रीय भाषाओं में हो। राधाकृष्णन आयोग की यह सिफारिश ही आगे चलकर स्कूली शिक्षा के लिए त्रिभाषा फार्मूला के नाम से मशहूर हुई। इस सिफारिश को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) ने 1964-66 में स्वीकार किया। इंदिरा गांधी की सरकार की ओर से पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में इसे शामिल किया गया। सरकार ने प्रस्तावित किया कि माध्यमिक स्तर तक हिंदी भाषी राज्यों में छात्र हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिणी भाषाओं में से एक और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी सीखें। राजीव गांधी सरकार में 1986 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नरेंद्र मोदी सरकार में 2020 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसी फार्मूले को रखा गया। लेकिन इसके क्रियान्वयन में लचीलापन लाया गया। पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विपरीत 2020 में बनी नीति में हिंदी का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें कहा गया है कि बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम 2 भारत की मूल भाषाएं हों। यह पहला मौका नहीं है जब तमिलनाडु में हिंदी विरोध की आड़ में राजनीतिक की जा रही है। हिन्दी का विरोध करना तमिलनाडु में वोट बैंक साधने का साधन बन चुका है। स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (डी.एम.के.) ही नहीं इससे पहले सत्ता में रहे अन्य क्षेत्रीय दल भी वोटों की खातिर हिंदी विरोध के मुद्दे को भुनाते रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों का इतिहास करीब सौ साल पुराना है। मौजूदा स्टालिन सरकार हिन्दी का जिस कदर विरोध कर रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कभी उतनी मुखर नहीं रही है। स्टालिन सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के, पोनमुडी और उनकी पत्नी पी. विसलाची को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि मंत्रियों पर लगे संगीन आरोपों के बावजूद मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक बार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान नहीं दिया, जबकि हिंदी का विरोध खूब कर रहे हैं।

एक ही प्रोफेशन में है लाइफ पार्टनर

तो आपके काम आएंगे ये टिप्स

आजकल के इस एडवांस समय में लोगों को सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं कुछ लोग साथ काम करते-करते एक-दूसरे को दिल दे बैठते है। इस मार्ड न टाइम में कई लोग ऐसे हैं जो कॉलीग भी हैं और कपल भी। ऐसी लाइफ के फायदे होने के साथ-साथ कई नुकसान भी है। कई बार प्रोफेशनल और प्रसनल लाइफ मिक्स होने के कारण रिश्ते में दूरियां आने लगती है। कई बार ऑफिस का प्रेशर और काम की झिकझिक पर्सनल लाइफ पर हावी हो ही जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्रोफेशनल लाइफ अलग रख कर आप अपनी पर्सनल लाइफ को एन्जॉय कर सकते है।

ऑफिस का काम

सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिस के काम को घर पर न लाएं। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ खरीब हो सकती है। चाहे कितना भी जरुरी काम क्यों न हो इसे ऑफिस तक ही रखें।

रोमांटिक डेट प्लान

अक्सर साथ-साथ काम करते-करते पार्टनर एक-दूसरे को डेट करना छोड़ देते है लेकिन ऐसा करने से आप अपना रिश्ता खुद तोड़ रहें है। साथ काम करने के बावजूद भी डेटिंग न छोड़े। इससे एक-दूसरे पर प्यार और विश्वास बना रहता है।

सलाह देना

ऑफिस में एक-दूसरे होने पर भी पार्टनर की सक्सेस को एन्जॉय करे। एक-दूसरे को मिली छोटी से छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं। ऐसे में आपके बीच का प्यार ओर भी बढ़ता है।

वीकेंड को एन्जॉय करना

ऑफिस से मिली छुट्टी को वेस्ट करने की बजाएं साथ में समय बिताएं। कहीं घूमने चले जाएं या घर पर ही एक-दूसरे से बाते करें। इससे आप अपने मन की बात बता और पार्टनर के मन की बात जान सकते है।

साथ में खाना

घर हो या ऑफिस हमेशा पार्टनर के साथ ही खाना खाएं। साथ बैठ कर खाना खाने से आपका रिश्ते और भी ज्यादा गहरा होगा और इससे आप दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा।

शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

लड़का- लड़की दोनों अपनी शादी को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि शादी के शुरुआती कुछ महीने सब ठीक रहता है पर जैसे- जैसे समय गुजरता जाता है जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। रिश्ते में पहले जैसी खुशी, उत्साह और प्यार न जाने कहां खो जाता है। एक रिश्ते को सफल बनाने के लिए जितना विश्वास जरूरी है उतना ही एक- दूसरे के साथ टाइम बिताना भी जरूरी होता है लेकिन आजकल लड़का और लड़की दोनों ही काम करते हैं जिसके कारण वह एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। इससे कई बार रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। आज हम आप कुछ ऐसे तरीके बाताएंगे जिनको अपनाकर आप आपने रिश्ते में पहले जैसा प्यार दोबारा जगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं तरीकों को बारे में।

आई लव यू कहना

कई बार आप सोचते हैं कि शादी को इतना टाइम हो गया अब अपने पार्टनर को आई लव यू बोलने से क्या होगा। यह सब काम तो बच्चे और न्यूली मैरिड कपल करते हैं पर ऐसा नहीं जब आप अपने पार्टनर को अपना प्यार दिखाओगे तो वह बहुत खूश हो जाएंगे। अपनी शादी को खूशहाल बनाने के लिए रोजाना सुबह उठकर आई लव यू कहें। इससे धीरे - धीरे आपके रिश्ते में आई खटास दूर हो सकती है।

डेट पर चलने के लिए कहें

अक्सर शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के बहाने ढंढूते रहते हैं लेकिन शादी बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जिससे कई बार रिश्ते खराब होने लगते हैं। अपनी शादी में फिर से वहीं प्यार लाने के लिए अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाएं।

गिफ्ट्स देना

पति और पत्नि दोनों को एक दूसरे को गिफ्ट्स देना चाहिए। चाहें कोई खास दिन हो या न अगर आप अपने पार्टनर को सरप्राइज देंगें तो बहुत खूश हो जाएंगे।

अतीत की बातें

अतीत की अच्छी बाते करें जैसे कब मिले थे, पहला गिफ्ट क्या था, कब आई लव यू बोला जैसी बाते करें कभी पास्ट की ऐसी बाते न करें जिससे दूसरे को कोई परेशानी हो। दूसरे के इमोशन को ध्यान में रखकर बात करने से शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो सकती है।

शिशु में जुकाम और बंद नाक की समस्या होना एक आम बात है। इस मौसम में शिशु को इंफैक्शन और जुकाम का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बड़े तो जुकाम होने पर बंक नाक की समस्या को झेल लेते है लेकिन बच्चों को इसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बंद हो जाए शिशु की नाक तो इन घरेलू तरीकों से करें इलाज

वैसे तो शिशु में सर्दी-जुकाम की समस्या को कुछ घरेलू तरीकों से दूर किया जा सकता है लेकिन कई दिनों तक ठीक न होने पर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आइए जानते है शिशु में नाक बंद होने के लक्षण और उसे पहचान दूर करने के घरेलू उपचार।

कैसे जानें कि शिशु के नाक बंद हैं?

शिशु की नाक बंद होने पर उनके सांस लेते समय घरघराहट की आवाज निकलती है। इसके अलावा सर्दी-जुकाम होने पर नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, दूध पीने में प्रॉब्लम और नाक लाल होने जैसी समस्याएं होती है।

- नाक बंद होने के कारण
- एलर्जी
- इंफैक्शन
- शरीर में बैक्टीरिया के कारण
- ठंड लगने के कारण
- साइनस इंफैक्शन के कारण

अपनाए ये घरेलू तरीके -

सरसों का तेल

शिशु को जुकाम होने पर उनकी नाक में सरसों के तेल की 2 बूंदें डालें। इससे जुकाम भी ठीक हो जाएगा और उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी।

भाप देना

सर्दी जुकाम होने पर शिशु को नहलाने की बजाए स्पंज स्नान कराएं। इसके अलावा सर्दी-जुकाम को दूर भगाने के लिए उन्हें भाप जरूर दिलवाएं।

नारियल तेल

शिशु की नाक बंद हो जाए, तो आप नारियल तेल को हल्का गर्म करके नाक में डाल दें। कुछ ही देर में शिशु की बंद नाक खुल जाएगी।

नींबू

4 नींबू के रस, छिलके और 1 चम्मच अदरक को फांके। इसमें पानी डालकर कुछ देर भिगो दें। इसके बाद इसमें उसी मात्रा में गर्म पानी और शहद मिक्स करके शिशु को पीलाएं।

अदरक

6 कप पानी में 1/2 कप बारिक अदरक, 2 छोटी दालचीनी को डालकर 20 मिनट तक पकाएं। इसे छानकर चीनी और शहद मिक्स करके बच्चे को पिला दें। एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह मिश्रण बराबर मात्रा में गर्म-पानी मिलाकर पिलाएं।

संतरे

संतरा इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर खांसी, गले में दर्द और नाक बहने की समस्या को दूर करता है। छोटे बच्चों को आप चम्मच की मदद से संतरे का रस भी पिला सकते हैं।

शिशु काफी नाजूक होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल करते समय काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। शिशु को स्पनतान बंद करने बाद अन्य चीजों की आदत डालते समय मां को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो महिलाओं को समझ भी नहीं आता कि शिशु को किन चीजों का सेवन करवाएं।

ब्रेस्टफीडिंग बंद करने के बाद शिशु को जरूर कराएं इन चीजों का सेवन

स्तनपान बंद करवाने के बाद बहुत जरूरी है कि शिशु ऐसी हेल्दी चीजों का सेवन करें जो उसे स्वस्थ बनाएं रखें। आज हम आपको ऐसे ही कुछ फूड के बारे में बताने जा रहें है जिन्हें आप स्तनपान बंद करवाने के बाद शिशु को दे सकती हैं। इनसे बच्चों की सेहत भी बन जाएगी और वो इसे आसानी से खा भी लेंगे।

हरी सब्जियां

शिशु को स्तनपान बंद करवाने के बाद आप उन्हें हरि सब्जियां जरूर खाने के लिए दें। मटर, पालक, गाजर, चुकंदर आदि को उबालकर मैश करके उसमें स्वादानुसार नमक मिला दें। इसे बच्चे आसानी से का भी लेंगे और उन्हें सब्जियां खाने की आदत भी पड़ जाएगी।

डेयरी प्रोडक्ट

जब शिशु स्तनपान छोड़ता है तो उसे पर्याप्त मात्रा पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में आप उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स भी दे सकती हैं। पनीर या दूध में मौजूद कैल्शियम शिशु को स्वस्थ रखते है।

फल

आप शिशु को सीजनल फल भी खाने के लिए दे सकती है। सेब, संतरे, केले, आम या किसी भी फल से शिशु को पर्याप्त मात्रा में फाइबर और मिनरल्स मिल जाएगा।

जूस

कई बार शिशु फल खाना पसंद नहीं करते या फिर उन्हें इसे चबाने में असुविधा होती है। ऐसे में आप उन्हें फल की बजाए उनका जूस दे सकती है। इसे वो पसंद भी करेंगे और उनके शरीर को जरूरी मिनरल्स भी मिल जाएंगे।

सूप

आप शिशु को सब्जियों का सूप बनाकर भी दे सकती हैं। इससे ना केवल उनको पोषण मिलेगा बल्कि उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।

बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और पहली टीचर उसकी मां। बच्चे जरा सी भी गलती करें तो सबसे पहले यही बात सुनने के मिलती है कि बच्चे घर में कुछ नहीं सिखाया गया। पढ़ाई के साथ-साथ कुछ बुनियादी शिष्टाचार सिखाने भी बच्चों को बहुत जरूरी हैं। इन्हीं में से एक है टेबल मैनर्स यानि दूसरों के साथ बैठकर किस तरह से खाना खाना है और कैसा व्यवहार करना जरूरी है। इससे बच्चे के साथ-साथ आपके व्यक्तित्व की भी पहचान होती है।

बच्चों को सिखाएं टेबल मैनर्स

बैठ कर खाने की आदत डालें

छोटे बच्चों के लिए एक जगह पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बच्चों को साथ बिठा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी कुर्सी आरामदायक हो। कुर्सी की ऊंचाई बच्चे की हाइट के मुताबिक हो, जिससे वह आराम से बैठ सके।

सही तरीके से खिलाएं खाना

आप मेहमानों के साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं तो बच्चों को नजरअंदाज न करें। बच्चों को बिना आवाज के खाना खाना सिखाएं। ज्यादा मुंह भरकर खाना न खिलाएं, निवाला सिर्फ उतना ही डालें, जितना वह आराम से खा सके। इसके अलावा प्लेट भर कर खाना न डालें, दोबारा जरूरत पड़ने पर खाना दोबारा सर्व करें।

बर्तनों का सही इस्तेमाल

डाइनिंग टेबल पर बैठते समय बच्चे को इस बात की जानकारी जरूर दें कि कौन सा बर्तन किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बड़े चम्मच को सूप और कटोरी का इस्तेमाल ग्रेवी वाली सब्जी के लिए किया जाता है।

खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में रखना

बच्चे को शुरू से ही यह आदत डालें कि घर अपना हो या किसी और का, खाना खत्म हो जाने के बाद हमेशा प्लेट को सिंक में रखें।

तारीफ भी करें

अपने बच्चे में इस बात की आदत भी डालें कि खाने के बाद खाना बनाने वाले की तारीफ भी करे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

खरगे के एक शब्द पर संसद में तनातनी, राज्यसभा में हंगामा

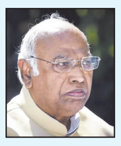

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने उपसभापति हरिवंश को कुछ ऐसा कह दिया, जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके लिए भाजपा ने उन पर जमकर निशाना साधा और माफी की मांग की। मामला बढ़ता देख मल्लिकार्जुन खरगे ने माफी भी मांग ली। उन्होंने हाथ जोड़कर सफाई दी। उन्होंने आसन को संबोधित करते हुए कहा कि आपको नहीं, सरकार को ठोकेंगे। हम सरकार की बात कर रहे थे। दरअसल, राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाह रहे थे। तभी उपसभापति ने उन्हें रोका। उपसभापति ने उनकी जगह कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को बोलने को कहा। इस बीच मल्लिकार्जुन खरगे अपनी सीट से उठे और बोलना शुरू कर दिया। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने तानाशाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने सीधे आसन की ओर इशारा करते हुए कहा कि तानाशाही चल रही है।

लैंड फॉर जॉब मामले में तेजप्रताप और हेमा को मिली जमानत

नईदिल्ली। बिहार के चर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में 11 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत उनके बड़े बेटे तेज प्रताज यादव और उनकी बेटी हेमा यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहे। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लालू परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी हेमा यादव और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव व अन्य को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 8 आरोपियों को पहले ही कोर्ट जमानत दे चुकी है। सुनवाई के दौरान आज भोला यादव कोर्ट में मौजूद थे। भोला यादव को रेगुलर बेल मिली है। इससे पहले इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दाखिल फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन भेजा था।

भाजपा विधायक के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव

पटना। बिहार के एक विधायक द्वारा मुसलमानों से होली पर घर से बाहर न निकलने की अपील पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य विधायक के पिता का है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि वे विधायक को फटकारें और उनसे माफी मंगवाएं। मधुबनी जिले के बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने अपनी टिप्पणी पर विस्तार से बताते हुए मीडिया से कहा कि टकराव से बचने के लिए मुसलमानों को होली पर घर पर ही रहना चाहिए। इस बार होली शुक्रवार (14 मार्च) को है और मुसलमान शुक्रवार को सामूहिक नमाज अदा करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया कि होली के मौके पर मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या यह पिता का राज्य है? वह कौन है? वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं?

औरंगजेब का गुणगान करने वाले अबू आजमी के बदले सुर

मुंबई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी के बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद जारी है। हाल ही में औरंगजेब को लेकर उनके बयान पर बवाल मचा था। वहीं, छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर अबू आसिम आजमी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद मामला और गरमाता जा रहा है। 11 मार्च को छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि था। इतिहास में दर्ज है कि आज ही के दिन मुगल शासक औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। अबू आसिम आज़मी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करके संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा: स्वराज्य के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। हालांकि, कुछ दिनों पहले औरंगजेब को लेकर दिए गए उनके बयान के कारण अब उनकी श्रद्धांजलि भी संदेह और विवाद के घेरे में आ गई है।

कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों और दंगाईयों के साथ : भाजपा

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद का बचाव करने और उसे निर्दोष कहने के लिए तीखी आलोचना की। सिंह ने दावा किया था कि खालिद को परेशान किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। खालिद के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा था कि जिस तरह से निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो बयान में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार आतंकवादियों और दंगाइयों का समर्थन करती रही है। पूनावाला ने कहा, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवादियों और दंगाईयों के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने उमर खालिद की जमानत याचिकाओं को बार-बार खारिज किया है।

मॉरिशस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, नवीन रामगुलाम ने लगाया गले

पोर्ट लुईस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरीशस पहुंचे। पोर्ट लुईस में पीएम मोदी का मॉरीशस में भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम समेत शीर्ष हस्तियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम नवीन ने पीएम मोदी को माला पहनाई और गले लगाकर उनका अपने देश में अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के साथ उप प्रधानमंत्री, मॉरीशस के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव, ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष और कई अन्य लोग भी मौजूद थे।

जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर कुल 200 गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें सांसद, विधायक, राजनयिक दल और धार्मिक नेता शामिल थे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्वीपीय देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे।

भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मॉरीशस पहुंच गया हूं। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम का हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए आभारी हूं। यह यात्रा एक मूल्यवान मित्र से मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर है। आज मैं राष्ट्रपति धरम गोखूल और प्रधानमंत्री रामगुलाम से मिलूंगा और शाम को एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करूंगा।

पीएम मोदी की मोदी की यह यात्रा मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान दोनों देश दक्षता विकास, व्यापार और सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।

मॉरीशस रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को कहा था कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया और उज्ज्वल अध्याय जोड़ेगी। पीएम मोदी मॉरीशस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे और द्वीपीय राष्ट्र के वरिष्ठ गणमान्य

व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। वह भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे तथा सिविल सेवा कॉलेज और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिनका निर्माण भारत की अनुदान सहायता से किया गया है।

पीएम मोदी ने मॉरीशस रवाना होने से पहले जारी एक बयान में कहा, मैं अपने 'सागर विजन' के तहत अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए अपनी स्थायी मित्रता को मजबूत करने तथा अपने सभी पहलुओं में अपनी साझेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से मॉरीशस नेतृत्व के साथ जुड़ने के अवसर की प्रतीक्षा में हूं। सागर से आशय सेक्युरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (क्षेत्र में सबके लिये सुरक्षा और विकास) से है। भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायु सेना की आकाश गंगा 'स्काईडाइविंग टीम' (मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस) समारोह में भाग लेगी।

पीएम मोदी ने कहा, हिंद महासागर में मॉरीशस एक करीबी समुद्री पड़ोसी, एक प्रमुख साझेदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। हम इतिहास, भूगोल और संस्कृति से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि गहरा आपसी विश्वास, लोकतंत्र के मूल्यों में साझा विश्वास और अपनी विविधता पर गर्व हमारी ताकत है। पीएम मोदी ने आखिरी बार 2015 में मॉरीशस का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को कारोबारी व रणनीतिक कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें साझा कर अपनी 27 साल पहले मॉरिशस यात्रा की यादें साझा की हैं। पीएम मोदी तब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे और पार्टी की ओर से अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में हिस्सा लेने मॉरीशस के मोका गए थे।

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, भारत और मॉरिशस के बीच इतिहास, वंश, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर का गहरा संबंध है। 1998 में जब वहां गया तो मिनी इंडिया में घर वापसी जैसा महसूस हुआ। एक सदी से भी पहले हमारे पूर्वज वहां मजदूर के तौर पर गए थे और अपने साथ तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस, हनुमान चालीसा और हिंदी भाषा लेकर गए थे। एक और रिश्ता है, 27 साल पहले नरेंद्र मोदी की पहली मॉरिशस यात्रा। पीएम मोदी 2 से 8 अक्तूबर 1998 के बीच मॉरिशस के मोका में अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने तब वहां अपने वक्तव्य में भगवान श्रीराम के सार्वभौमिक मूल्यों के बारे में बात की और बताया कि कैसे रामायण भारत और मॉरिशस को एक शाश्वत सभ्यतागत रूप से जोड़ने वाले सेतु के रूप में काम करती है। उस यात्रा में मुरली मनोहर जोशी से भी उनकी मुलाकात हुई थी।

भारत में विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत मॉरीशस

मॉरीशस में 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भारत और मॉरीशस के बीच समुद्री सुरक्षा, विकास, क्षमता निर्माण में करीबी सहयोग है और लोगों के आपसी संबंधों काफी मजबूत हैं। यह नजदीकी खासकर उन विकास परियोजनाओं में दिखती है, जो भारत की मदद से मॉरीशस में बनाई गई हैं। भारत मॉरीशस का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। 2023-24 में मॉरीशस, सिंगापुर के बाद भारत में विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

दोनों देशों ने फरवरी 2021 में एक व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों के बीच 15 वर्षों की वार्ता के बाद हुआ था। यह भारत और किसी अफ्रीकी देशे के बीच पहला व्यापारिक समझौता था।

मनरेगा फंड को लेकर सत्ता पक्ष से भिड़े टीएमसी सांसद

नई दिल्ली। मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस समय काफी हंगामा देखने को मिला, जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सत्ता पक्ष से भिड़ गए। दरअसल मनरेगा फंड को लेकर कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। लोकसभा अध्यक्ष ने किसी तरह मामले को संभाला।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सवाल किया कि मनरेगा योजना के लाभ उनके राज्य पश्चिम बंगाल को क्यों

नहीं मिल रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि लगातार मंत्रालय कह रहा है कि 25 लाख फर्जी मामलों का पता चला है। हम कह रहे हैं कि अगर फर्जी मामलों का पता चला है तो कार्रवाई करें, जांच करें और जो गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए, लेकिन आप 25 लाख मामलों के चलते 10 करोड़ लोगों का फंड नहीं रोक सकते।%

कल्याण बनर्जी ने अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि %आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा है...आपको किसने मंत्री बनाया? कल्याण बनर्जी की इस टिप्पणी पर तुरंत सत्ता पक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और टीएमसी सांसद की टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल्याण बनर्जी की भाषा पर सवाल उठाए। हंगामा बढ़ते देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील की कि वे आसन को संबोधित करें और एक दूसरे पर टिप्पणी न करें। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि अपने शब्दों का पूरी सावधानी से इस्तेमाल करें, अगर कोई कुछ अनाधिकारिक तौर पर कह रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया न दें।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 25 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड का पता चला है और जो फंड गरीब लोगों के लिए था, उसे टीएमसी के कैडर ने लूटा। वित्त मंत्री के इसी बयान पर मंगलवार को कल्याण बनर्जी ने टिप्पणी की, जिसके बाद हंगामा हुआ।

लोकसभा में पेश हुआ इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल

नईदिल्ली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किया। विधेयक में भारत के आव्रजन कानूनों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है। नया विधेयक पारित होने के बाद, यह औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेगा, जिसमें विदेशी अधिनियम, 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 शामिल हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, आव्रजन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना और प्रवेश और ठहरने की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशियों पर सख्त दंड लागू करना है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नियमों का हवाला देते हुए विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तिवारी ने कहा कि इस विधेयक को वापस लिया जाए या फिर जेपीसी को भेजा जाए ताकि इस पर गहन विचार-विमर्श किया जा सके।

खेल
प्रमुख समाचार

2023 से आईसीसी टूर्नामेंट में भारत का चल रहा है दबदबा

नई दिल्ली। रोहित शर्मा की अगुआई में भारतीय टीम का 2023 से आईसीसी टूर्नामेंट में दबदबा देखने को मिला है। भारत ने अक्तूबर 2023 से मार्च 2025 तक कुल 24 मैच खेले हैं जिसमें से 23 मुकाबले जीते हैं। आईसीसी के पिछले तीन सीमित ओवर के टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपना दबदबा बनाने में सफल रही है। भले ही हुए 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में हार मिली, लेकिन इसके बाद वह लगातार दो खिताब जीतने में सफल रहा है।

भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। यह भारत की सातवीं आईसीसी ट्रॉफी है। इससे पहले टीम 1983 और 2011 वनडे विश्व कप, 2007 और 2024 टी20 विश्व कप और 2002, 2013 और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुकी है। भारत इस पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा। उसने लगातार पांच मैच जीते थे। भारतीय टीम का पिछले कुछ समय में आईसीसी टूर्नामेंट में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उससे वह उन चुनिंदा टीमों में शामिल हो गया है जिसने आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपना दबदबा कायम किया था। भारत की इस विजयी गाथा की शुरुआत होती है अक्तूबर 2023 में जब टीम घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने उतरी। वनडे विश्व कप राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला गया था जिसमें सभी 10 टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना था। भारत ने ग्रुप चरण में सभी नौ और फिर सेमीफाइनल जीता, इससे टीम लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची। खिताबी मुकाबले में हालांकि, उसे ऑस्ट्रेलिया से हार मिली और उसका विजयी अभियान रुक गया। भारत को यह हार काफी खली क्योंकि टीम 2011 के बाद एक बार फिर विश्व विजेता बनने के बेहद करीब थी। इसके सात महीने बाद जून 2024 में भारत रोहित की ही कप्तानी में टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने अमेरिका और वेस्टइंडीज गया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

मार्केट में शानदार रिकवरी सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा उछला

नईदिल्ली। सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में आज (11 मार्च) उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। आज 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 73,743.88 पर खुला था, जो 74,195.17 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अंत में यह 12.85 (0.02%) की गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 22,345.95 पर खुला था, जो 22,522.10 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इसके बाद अंत में यह 37.60 (0.17%) चढ़कर 22,497.90 पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.7% की बढ़ोतरी हुई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट आई। निफ्टी में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले शेयरों में ट्रेंट, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस और बीपीसीएल शामिल थे। वहीं, सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड कॉर्प और एमएंडएम शामिल था।

सेंसेक्स दिसंबर 2025 तक छू सकता है 105,000 का लेवल

नईदिल्ली। भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में गिरावट का दौर है। जियो-पॉलिटिकल टेंशन और डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का असर देखने को मिल रहा है। इस बीच, मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि भारतीय बाजार में तेजी आएगी और बुल-केस में दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स 105,000 तक पहुंच सकता है। यह मौजूदा स्तर से करीब 41 फीसदी ज्यादा है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि भारतीय बाजार में निवेश फायदेमंद हो सकता है। रिस्क-रिवार्ड फेवरेबल हो रहा है और बेस केस में सेंसेक्स दिसंबर 2025 तक 93,000 के लेवल टच कर जाएगा। यह मौजूदा स्तर से करीब 25 फीसदी ज्यादा है। बियर केस में सेंसेक्स साल के आखिर तक 70,000 के स्तर तक गिर सकता है। यह मौजूदा स्तर से लगभग 6 फीसदी नीचे है।

लगातार तीसरे महीने निवेशकों को भाया गोल्ड ईटीएफ

नईदिल्ली। गोल्ड के लिए नए साल का दूसरा महीना भी शानदार रहा। फरवरी के दौरान लगातार तीसरे महीने इन्वेस्टमेंट डिमांड में तेजी देखने को मिली। गोल्ड ईटीएफ के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के दौरान ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश 9.4 बिलियन डॉलर बढ़ा। मार्च 2022 के बाद इन्वेस्टमेंट डिमांड में यह सबसे बडी मासिक बढ़ोतरी है। वॉल्यूम /होल्डिंग के लिहाज से इस दौरान निवेश में 99.9 टन की वृद्धि हुई। सोने की कीमतों में तेजी और लगातार तीसरे महीने आए इनफ्लो के दम पर फरवरी 2025 के अंत तक गोल्ड ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम बढ़कर रिकॉर्ड 306 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। टोटल होल्डिंग भी पिछले महीने के अंत तक 3,353 टन पर दर्ज किया गया जो जुलाई 2023 के बाद सबसे ज्यादा है।

एडलवाइस म्युचुअल फंड ने लॉन्च किया लो ड्यूरेशन फंड

नईदिल्ली। एसेंट मैनजमेंट कंपनी एडलवाइस म्युचुअल फंड ने मंगलवार (11 मार्च) को एडलवाइस लो ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया। यह एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है, ताकि पोर्टफोलियो की मैकॉले ड्यूरेशन 6 से 12 महीने के बीच बनी रहे। इस स्कीम में तुलनात्मक रूप से हाई ब्याज दर जोखिम और मध्यम क्रेडिट जोखिम होता है। एडलवाइस का यह न्यू फंड ऑफर 11 मार्च से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। निवेशक 18 मार्च 2025 तक इस न्यू फंड ऑफर में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में निवेशक मिनिमम रू. 100 से निवेश शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। प्रणवी कुलकर्णी और राहुल देधिया इस स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं।

अमरीकी टैरिफ का भारत पर क्या असर : मिलियन-डालर का सवाल

कल्याणी शंकर

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा ने नई दिल्ली में गंभीर ड्क्षचता पैदा कर दी है। अमरीकी वस्तुओं पर भारत के उच्च आयात कर लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं, जो अब व्यापार भागीदारों को प्रभावित कर रहे हैं।

यह कदम अपने परिणामों के बिना नहीं है। यह आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे निर्यात को जोखिम में डालता है जिससे भारत को सालाना 7 बिलियन डालर का महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। सवाल यह है कि इस व्यापार युद्ध से भारत को कितना नुकसान होगा? क्या नई दिल्ली नुकसान होने से पहले कोई रास्ता निकाल सकती है? यह मिलियन-डालर का सवाल नीति निर्माताओं और व्यापार विशेषज्ञों को चौकन्ना रखता है, जो स्थिति की संभावित गंभीरता को रेखांकित करता है।

भारत वर्तमान में अमरीकी उत्पादों पर अमरीका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात कर की तुलना में कहीं अधिक आयात कर लगाता है तथा दोनों के बीच 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार, यदि अमरीका इन टैरिफ को कम करता है, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का अमरीका को निर्यात 2 बिलियन डालर घटकर 7 बिलियन डालर रह सकता है। भारत का अमरीका के साथ 36 बिलियन अमरीकी डालर से ज्यादा का व्यापार अधिशेष है। अमरीका को भारतीय निर्यात का हिस्सा 2019-20 में 16.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 17.7 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रशासन द्वारा टैरिफ कार्रवाई की जा सकती है। अपने अभियान

के दौरान ट्रम्प ने कई अमरीकी निर्यातों पर भारतीय टैरिफ की आलोचना की और भारतीय निर्यातों पर पारस्परिक कर लगाने की संभावना का उल्लेख किया। ट्रम्प का मानना है कि अब समय आ गया है कि अमरीका टैरिफ का इस्तेमाल करके निष्पक्ष व्यापार करे। ट्रम्प प्रशासन के तहत, आपको टैरिफ देना होगा और कुछ मामलों में, लागत उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी। ट्रम्प इस बात पर जोर देते हैं कि अमरीका अब अनुचित व्यापार प्रथाओं को स्वीकार नहीं करेगा। भारत अमरीकी वस्तुओं पर उच्च आयात कर लगाता है। भारत 100 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, जिससे संयुक्त राज्य अमरीका के लिए अनुचित व्यापार प्रणाली बनती है।

2 अप्रैल को पारस्परिक शुल्क, अर्थात भारत द्वारा लगाए गए शुल्क, अमरीका द्वारा भी लागू कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि भारत अमरीकी बाजार में पहुंच को सीमित करने के लिए गैर-मौद्रिक शुल्क का उपयोग करता है, तो अमरीका भी उसी प्रकार के प्रतिबंध लागू करेगा। 2 अप्रैल को पारस्परिक शुल्क लागू किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि भारत द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क का यू.एस. द्वारा मिलान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि भारत यू.एस. बाजार पहुंच को सीमित करने के लिए गैर-मौद्रिक शुल्क का उपयोग करता है, तो यू.एस. समान प्रतिबंध लागू करेगा। क्रिसिल इंटैलीजैंस की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत के निर्यात पर इन टैरिफ कार्रवाइयों के संभावित नुकसान को रेखांकित किया, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22 प्रतिशत है।

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार, भारत का यू.एस. के साथ टैरिफ गैप बहुत बड़ा है। यदि यू.एस. टैरिफ को समान करने का निर्णय लेता है, तो भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत में उद्योग और व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि राष्ट्रपति भारत के शीर्ष निर्यात जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, हीरे, आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स को अमरीका में आयात नहीं कर सकते। विश्लेषकों का कहना है कि सबसे अधिक असुरक्षित रसायन, धातु उत्पाद और आभूषण हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पाद हैं। भारत को अपने संभावित लाभों का आकलन करना चाहिए और भविष्य की व्यापार चुनौतियों के लिए नवीन रणनीति विकसित करनी चाहिए।

सदन में कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव

खुले बाजार में सरप्लस धान बेचने से होगा भारी नुकसान

रायपुर। विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि खरीफ विपणन वर्ष (केएमवाई) 2024-25 में खरीदे गए अधिशेष धान को खुले बाजार में बेचने के छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान होगा।

कांग्रेस सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राज्य के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल द्वारा उनके आरोपों का जवाब देने के बाद अध्यक्ष ने मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आ गए और उन्हें निलंबित कर दिया गया।

शून्यकाल में उठा धान खरीदी का मुद्दा- शून्यकाल में धान खरीद का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की खरीद योजना के तहत केएमवाई 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 149.24 लाख टन धान खरीदा है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, खरीदे गए धान से केंद्र और राज्य पूल को चावल की आपूर्ति करने के बाद, राज्य के पास 40 लाख टन अधिशेष बचेगा।

महंत ने कहा कि राज्य सरकार ने निविदा आमंत्रित करके इस अधिशेष धान को खुले बाजार में बेचने का फैसला किया है. कांग्रेस विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव नोटिस में बताया कि पंजाब में किसानों से समर्थन मूल्य पर 172 लाख टन धान खरीदा गया था और केंद्र ने पूरा स्टॉक स्वीकार कर लिया।

उन्होंने आगे सवाल किया कि केंद्र छत्तीसगढ़ से अधिशेष चावल क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है. कांग्रेस सदस्यों ने दावा किया कि खुले बाजार में 40 लाख टन धान बेचने से राज्य के खजाने को 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरप्लस धान पर कांग्रेस का दावा- कांग्रेस सदस्यों ने दावा किया कि खुले बाजार में 40 लाख टन धान बेचने से राज्य के खजाने को 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया. उन्होंने जानना चाहा कि क्या केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत नुकसान की भरपाई करेगा और अपने स्थगन प्रस्ताव नोटिस पर चर्चा की मांग की. स्पीकर रमन सिंह ने सदन में उनका नोटिस पढ़ा और कहा कि राज्य के खाद्य मंत्री बयान देंगे।

मंत्री दयालदास बघेल ने दिया जवाब- विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 149,24,710 लाख टन धान खरीदा गया. उन्होंने कहा कि केंद्र के खाद्य विभाग ने राज्य को केंद्रीय पूल में 70 लाख टन चावल खरीदने की अनुमति दी है।

उन्होंने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम राज्य पूल के तहत 13.34 लाख टन चावल खरीदेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए चावल को रेलवे के जरिए दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद के लिए किसानों को 46,277 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और इस राशि में एमएसपी के अलावा कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के लिए इनपुट सहायता भी शामिल है.40 लाख टन सरप्लस धान की होगी नीलामी- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 40 लाख टन की सीमा तक अधिशेष धान को नीलामी के माध्यम से बेचने का फैसला किया है।

भावना बोहरा ने सदन में उठाए बारदाना, धान खरीदी और राशन योजना के मुद्दे

रायपुर । पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने धान खरीदी, बारदाने की उपलब्धता, रेडी टू ईट योजना और अंत्योदय खाद्यान्न योजना से जुड़ी समस्याओं को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से बारदाने की कमी, किसानों को दिक्कतें और वैकल्पिक समाधान को लेकर सवाल किए।

भावना बोहरा ने पूछा कि धान खरीदी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कितने बारदाने खरीदे गए और उनकी लागत क्या थी? खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि 2023-24 में 18.35 करोड़ नए बारदाने और 3.29 करोड़ बारदाने पीडीएस दुकानों से खरीदे गए। वहीं, 2024-25 में 37.31 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन केवल 26.35 करोड़ बारदाने ही खरीदे जा सके।

भावना बोहरा ने बारदाने की कमी से किसानों को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई और जूट उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजना की मांग की। उन्होंने निजी क्षेत्र से सस्ते बारदाने खरीदने के विकल्प पर भी सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि खरीद केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार जूट कमिश्नर से की जाती है।

उन्होंने पूछा कि पंडरिया विधानसभा में कितनी मात्रा में धान खरीदा गया और उसका उठाव कितना हुआ? खाद्य मंत्री ने बताया कि 10 फरवरी 2025 तक 3,31,611.76 मीट्रिक टन धान

की खरीदी हुई, जिसमें से 1,57,134.46 मीट्रिक टन का कस्टम मिलिंग हो चुका है और 64,090.93 मीट्रिक टन धान अब भी उपार्जन केंद्रों में पड़ा हुआ है।

अंत्योदय अन्न योजना की स्थिति

भावना बोहरा ने अंत्योदय अन्न योजना को लेकर सवाल किया कि कबीरधाम जिले में कितने अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं और उन्हें कितना राशन मिला? खाद्य मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में 64,688 राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें 21,380 टन चावल, 644 टन शक्कर, 661 टन नमक और 203 टन चना वितरित किया गया है।

रेडी टू ईट योजना पर सवाल

महिला एवं बाल विकास विभाग से उन्होंने पूछा कि रेडी टू ईट योजना प्रदेश में कितने चरणों में लागू होगी और कबीरधाम जिले में इसे कब लागू किया जाएगा? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि पहले चरण में यह योजना बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर में लागू होगी। बाकी जिलों में पहले चरण की सफलता के बाद इसे लागू किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने महिला-बाल विकास मंत्री को घेरा...

रायपुर । विधानसभा बजट सत्र में सदन में महतारी वंदन योजना का मुद्दा गर्माया। विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल पूछते हुए जानकारी मांगी वहीं इस दौरान मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। जिसके बाद जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी की। साथ ही सदन से विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया।

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा- योजना शुरू होने के बाद ऐसे कितने पात्र हितग्राही है, जिन्हें एक भी किश्त नहीं मिली। जिसके जवाब में मंत्री राजवाड़े ने कहा- 3 हजार 971 लोगों को एक भी किश्त नहीं मिली है। बैंक खाते सीडिंग नहीं होने, असक्रिय खातों की वजह से भुगतान नहीं हो पाया है। जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने कहा- तीन हज़ार से अधिक लोगों की राशि कहा जा रही है। वहीं मंत्री राजवाड़े ने कहा- तकनीकी खामियों को दूर कर भुगतान किया जाएगा। उमेश पटेल ने कहा- एक साल तक एक भी किश्त नहीं दी गई। क्या सभी 3 हजार 971 लोगों को पिछले एक साल की किश्त एक साथ दी जाएगी। जिसके बाद आसंदी से रमन सिंह ने कहा- पुराना पैसा नहीं मिलता है।

बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में उबाल, मोदी सरकार पर किया अटैक

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सोमवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लामबंद हुए, ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी के द्वारा कार्रवाई का आरोप लगा रही है। कांग्रेस जिला मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटे। उसके बाद रैली निकाली फिर ईडी का पुतला जलाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के जवानों के बीच हाथापाई भी देखने को मिली।

ईडी के खिलाफ की गई नारेबाजी- इस विरोध प्रदर्शन के लिए सबसे पहले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रायपुर कांग्रेस जिला कार्यालय के पास जुटे. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहले ईडी के खिलाफ नारे लगाए. उसके बाद सभी कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटे. वहां से एक रैली निकालकर सभी नगर निगम चौक के पास पहुंचे. यहां पर कांग्रेसियों ने पुतला जलाया. कांग्रेसियों ने ईडी को बीजेपी सरकार की कठपुतली करार दिया।

पुलिस ने पुतले को बुझाया- इस आग के बाद पुलिस ने पुतले को बुझाने का काम किया. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली. इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे भी शामिल थे. गिरीश दुबे ने कहा कि सोमवार को हमारे नेता भूपेश बघेल के यहां ईडी ने छापा मारा. इस दौरान ईडी को वहां कुछ नहीं मिला. कार्रवाई की कोई सीमा है या नहीं, ईडी को इसे स्पष्ट करना चाहिए.

पूछना चाहते हैं कि 2020 से लगातार छापे पड़ रहे हैं. क्या जीवन भर ईडी इसी तरह से छापे मारती रहेगी. वह हमें ऐसे ही प्रताड़ित करती रहेगी. किस विषय में छापा मारा गया है, किस विषय में कार्रवाई की गई और उसके लिए कोई समय सीमा है या नहीं . यह कार्रवाई कितने समय तक चलेगी, यह ईडी को बताना चाहिए- गिरीश दुबे, कांग्रेस के रायपुर जिला अध्यक्ष

कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक- इस दौरान कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर अटैक भी किया गया. गिरीश दुबे ने कहा कि बीजेपी छटपटाई हुई है. भूपेश बघेल को कोर्ट ने सीडी कांड से बरी किया. इस मामले को लेकर कांग्रेस विधानसभा में लगातार सवाल उठा रही है. ईडी सिर्फ प्रताड़ित करने का काम कर रही है. इसलिए हमने ईडी का पुतला जलाया है.

कन्या विवाह आयोजन में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव, व मंत्री कश्यप

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मंगलवार को सुकमा जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक कन्या विवाह एवं क्षेत्रीय सरस मेला में सम्मिलित होकर विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर शुभकामनाएं दीं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज में बेटियों को सम्मान और सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उनके भविष्य को सशक्त और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। हमारी सुशासन सरकार बेटियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। श्री देव ने इस सफल आयोजन के लिए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप सहित क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

डीएमएफ घोटाला : रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी गए जेल...

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज निधि घोटाला मामले में निलंबित ब्रूर अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया, माया वारियर और मनोज द्विवेदी और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को जेल भेज दिया गया। विशेष कोर्ट ने 19 मार्च तक सभी की रिमांड बढ़ा दी है। वहीं, जेल में बंद आरोपी सौम्या चौरसिया ने जमानत याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगली

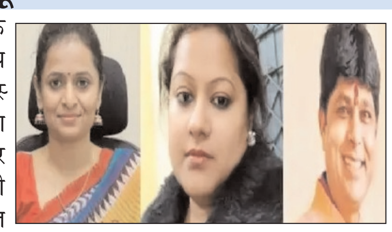

सुनवाई 17 मार्च को होगी।

ईडी ने 23.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी: ईडी ने पिछले साल 11 दिसंबर को निलंबित ब्रूर अधिकारी रानू साहू, माया वरियर और अन्य के 23.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें 21.47 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल थी, जिसे डीएमएफ घोटाले से अर्जित काले धन से खरीदा गया था।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

चैतन्य बघेल को ईडी का समन, 15 मार्च को होगी पूछताछ...

रायपुर । शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को समन भेजा है। चैतन्य बघेल को 15 मार्च को ईडी दफ्तर में तलब किया गया है। इस दौरान ईडी चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। सोमवार को ईडी ने बघेल

निवास सहित 14 ठिकानों में छापेमारी की थी। सोमवार को भूपेश बघेल के एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर ब्रह्म ने दबिश दी थी। भिलाई-3 स्थित वसुंधरा नगर निवास और रायपुर निवास पर शराब घोटाला मामले में ब्रह्म ने रेड मारी थी। दो गाड़ियों में पहुंची अफसरों की टीम घर पर कई दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल से पूछताछ भी हुई। प्रदेशभर के 14 जगहों पर ब्रह्म ने कार्रवाई की थी। रेड को लेकर ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें कहा गया कि, ईडी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के संबंध में 14 स्थानों पर पीएमएलए के तहत तलाशी ले रहा है। जिसमें उनके बेटे चैतन्य बघेल का आवास और करीबी सहयोगी भूपेश बघेल, पुत्र, लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ ??पप्पू बंसल का आवास भी शामिल है। ईडी को पता चला है कि, चैतन्य बघेल शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय के प्राप्तकर्ता भी हैं। जिसमें अपराध की कुल आय लगभग 2161 करोड़ रुपये है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निकाला गया है।

होली पर थानों में 70 से ज्यादा बदमाशों की परेड...

रायपुर । आगामी होली त्योहार के दौरान अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने 11 मार्च को 70 से अधिक चाकूबाजों, हिस्ट्रीशीटरों और आपराधिक तत्वों को क्राइम ब्रांच में तलब किया। अपराधियों की परेड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक संजय सिंह और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पांडेय की निगरानी में हुई। पुलिस अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की हुड़दंग या अपराध में संलिप्त न रहें। साथ ही, उनसे अपराधी प्रवृत्ति के अन्य व्यक्तियों की जानकारी देने को भी कहा गया। अब तक 470 से अधिक चाकूबाजों और हिस्ट्रीशीटरों को पुलिस ने बुलाकर सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें और होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में सहयोग करें।

बघेल सौम्या चौरसिया के बारे में बोल के दिखाए : संजय

रायपुर । भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की जाँच को लेकर कांग्रेस के आचरण पर तीखा हमला बोला है। श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस को देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है। जाँच एजेंसियों पर हमला करके कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शित किया कि उन्होंने कुछ गलत किया है,

इसीलिए दबाव बनाने के लिए हिंसा तक पर उतारू हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाले भूपेश बघेल सौम्या चौरसिया के नाम पर चुप्पी क्यों साध लेते है? वो उनकी उपसचिव रही, 2 साल से जेल में है। पत्रकार अगर सौम्या के बारे में सवाल पूछते हैं तो कांग्रेसी उन्हें घेरकर मारपीट करने की कोशिश करते हैं। भूपेश बघेल में दम है, तो दो शब्द सौम्या चौरसिया पर बोल के दिखाएँ,फिर बड़ी-बड़ी बातें करें। यदि कोई संवैधानिक संस्था जाँच एजेंसी किसी मामले में कोई कार्रवाई कर रही है और आरोपित व्यक्ति को यदि अपने ऊपर भरोसा है गलत नहीं किया है, तो उन्हें शांति के साथ कार्रवाई होने देना चाहिए। लेकिन, जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने दबाव बनाने के लिए अपनी संस्कृति और राजनीतिक चरित्र के अनुरूप, अपनी आदत के अनुरूप पथराव करके जाँच एजेंसी पर हमला किया।

सूखे रंग और गुलाल से आँखों को बचाएं : डॉ. दिनेश मिश्र

रायपुर। वरिष्ठ नेत्र एवं कान्टेक्ट लेन्स विशेषज्ञ डॉ. दिनेश मिश्र ने होली पर आंखों व अन्य संवेदनशील अंगों को बचाकर रंग खेलने का सलाह दी है। उन्होंने कहा कि होली खेलें जरूर पर आंखों के अंदर में सूखा रंग व गुलाल न जाए, इसका

विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया कि पहले होली प्राकृतिक वस्तुएं जैसे विभिन्न फूलों, पत्तियों, जड़ों व बीजों से तैयार रंगों से खेली जाती थी जो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं थे, इन रंगों के तैयार करने में भले ही समय अधिक लगता था तथा कम मात्रा में ही तैयार होते थे। लेकिन ये शारीरिक वातावरण के अनुकूल थे। आजकल बाजार में उपलब्ध रंग-गुलाल कृत्रिम व रासायनिक पदार्थों से बनते है।, जो कम समय में तथा अधिकाधिक मात्रा में बनते हैं, कृत्रिम रंग सस्ते जरूर हैं लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचा सकते है। कृत्रिम रंग जिन रासायनिक पदार्थों से बनते है उनके रासायनिक गुणों के अनुरूप अम्लीय-क्षारीय होते हैं। ये केमिकल (रसायन) शरीर की त्वचा, पलकों, आंखों पर दुष्प्रभाव डालते हैं जिससे आंखों व चेहरे में जलन, खुजलाहट, सूजन, दाने आना, एलर्जी होना आदि प्रतिक्रिया होती है। यह प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न हो सकता है।

कलेक्टर ने दिया राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा में शामिल होने का न्योता

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज शिक्षार्थियों को राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्योता दिया। ऐसे सभी शिक्षार्थी जिन्होंने साक्षरता कक्षा में 200 घंटे प्रवेशिका के 7 अध्याय की पढ़ाई पूर्ण की है को यह निमंत्रण दिया गया। यह परीक्षा राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा का आयोजन 23 मार्च 2025 दिन रविवार को होगी। इसका समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिक्षार्थियों के सुविधानुसार चिन्हांकित केंद्रों में आयोजित की जा रही है। महापरीक्षा में शिक्षार्थियों को शत प्रतिशत सम्मिलित करने हेतु कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने सभी को परीक्षा में सम्मिलित होकर सफल होने हेतु शुभकामनाएं दी।

मंत्री देवांगन के विभागों के लिए 965 करोड़ की अनुदान मांगें पारित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 965 करोड़ 18 रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 हजार 9 हजार रूपए शामिल हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा 01 नवंबर 2024 से छत्तीसगढ़ की विकास नीति 2024-30 लागू की गयी है। इसका मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य ने अपनी नीति को विकास का आधार बनाकर रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया है। इसके लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जो अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं। विशेषकर, जो इकाइयाँ 1000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगी, उन्हें मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इकाईयों के द्वारा दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार दिये जाने पर इस विषय पर विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।

देवांगन ने सदन में बताया कि स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान जैसे विभिन्न अनुदान एवं छूट प्रदान किए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में भूमि, भवन एवं बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क भुगतान से पूर्ण छूट एवं 06 वर्ष से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्व-घोषणा को मान्य किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री

देवांगन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 34 औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना की जा चुकी है एवं आने वाले समय में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न जिलो में नवीन फूड पार्क, रायपुर जिले में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क और प्लास्टिक पार्क, नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इण्डिया योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2024-30 में युवाओं के लिये एक नई योजना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

देवांगन ने सदन में बताया कि राज्य की औद्योगिक इकाईयों के अनुदान/छूट के संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए, सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिना ठोस तैयारी के उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. कर दिये जाते थे, जिससे राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार एम.ओ.यू. के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट जारी कर रही है। यह उन निवेशकों को दिया जाता है जो निवेशक हमारी औद्योगिक नीति एवं अनुदान प्रोत्साहन से प्रभावित होकर राज्य में निवेश करने की अभिरूचि लिखित में प्रस्तुत करते हैं। इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट केवल एम.ओ.यू. का विकल्प पत्र नहीं है, बल्कि यह विस्तृत चर्चा उपरांत निवेशकों को दिया जाने वाला विश्वास पत्र है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास नीति लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक के कुल 31 प्रस्ताव निवेश के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

देवांगन ने बताया कि पोलीमेटेड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने राज्य में 1143 करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नवा रायपुर में इसका प्लांट बनने जा रहा है। इसी तरह यस फैन एण्ड एल्लाईन्सेस और रेक बैंक डाटा सेंटर ने भी नवा रायपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन का चयन कर लिया है। अब्रेल ग्रीन एनर्जी ने मुंगेली में सोलर पावर के लिए भूमि का चयन किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए विभिन्न अनुदानों एवं छूटों का प्रावधान किया गया है। नये बजट में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नया रायपुर में कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ ही रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। इससे व्यापारिक संगठनों को एक मजबूत मंच मिलेगा और वे राज्य में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.